भीलवाड़ा मंगलवार,12,नवम्बर, 2024

RNI NO. RAJHIN/2016/74127

नमस्ते राजस्थान

वर्ष : 09, अंक: 18 | E-Mail: namasterajasthan11@gmail.com, nrnews100@gmail.com | भीलवाड़ा संस्करण | पृष्ठ 08 मूल्य 4 रुपए हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र | मो. 9214417111, 8005910698

मौलाना बोले-मुसलमानों की लिंचिंग करने वालों को सरकार बचाती है

अजमेर के सरवर चिश्ती ने कहा- मैं हेट स्पीच देता हूं, उनको मोदी की स्पीच नजर नहीं आती

नमस्ते राजस्थान

जयपुर जयपुर में रविवार को तहफ्फुज औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वक्फ के संबंधित जन जागृति लाने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इसमें इत्तेहादे ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने मौलाना तौकीर रजा ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा- मैं तमाम मुसलमान से कहना चाहता हूं। एक साथ आओ दिल्ली का घेराव करते हैं। पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है। 24 तारीख को हमारा दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है। अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को तवज्जो देंगे। हमें अपनी ताकत दिखानी है। अपनी बात मनवानी है। उन्होंने कहा- दिल्ली तक तुम्हें आना है। यदि दिल्ली तक तुम आते हो तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन बेइमान बदमाशों ने जो गुस्ताखी की है। इनकी गिरफ्तारी इसी पार्लियामेंट के सेशन में होगी। इसके खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा। कानून बनाया जाएगा की रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने आगे कहा- मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, मुसलमानों की लिंचिंग करवाओ, रसूल की शान में गुस्ताखी कर दो बहुत वायरल होता है। बहुत लाइक मिलते हैं। बेईमान सरकार उन्हें बचाती है। उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं इसके खिलाफ कानून बनवाओं।

वक्फ कानून पर बोले

मौलाना तौकीर रजा ने कहा- किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। मैं कहता हूं तुम आओ 24 तारीख को बात होगी। दिखाया जाएगा आज हम तिरंगा लेकर आए हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। कानून के दायरे में आए हैं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे। उस दिन फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हम अपने तरीके से आएंगे। हमारी तादाद छुपाते हो जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा- हम स्ट्रगलर हैं, अपने मजहब के लिए। अपने मुल्क के लिए जद्दोजहत करते हैं। हमारे नौजवान बुजदिल नहीं है। हमारे लोगों ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन यह नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इनको कब्जे में कर सको।

मोबाइल वो शैतान जो कानों से घुसता है, दिल में जगह बना लेता है

उन्होंने कहा- मेरी बहुत सी बातों पर लोगों ने तवज्जो नहीं दी। बहुत सी बातें ऐसी हुई, जो मैंने पहले ही कहीं। मैंने कहा था मोबाइल अपनी बच्चियों को मत दो। यह ऐसा शैतान है। जो कानों से घुसता है। दिल में जगह बना लेता है। मोबाइल जिस बच्ची के पास है। वह हमारे सामने है, लेकिन किस हद में है। हमें नहीं पता। उस वक्त इंटरनेट भी इतना आम नहीं हुआ था। तब से मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन मेरी बात को तवज्जों नहीं दी गई। नतीजा सबकी जड़ में मोबाइल है।

उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- हमारे साथ जो न इंसाफी हो रही है। बेईमानियां हो रही है। अभी भी उसके फैसला आपके सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुलडोजर चलाएं। बुलडोजर चलाने वालों को 25-25 लाख मुआवजा देने के लिए पाबंद किया गया है। 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बिल्डिंग ने कोई जुर्म नहीं किया। तू अपने देश की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला रहा है। अपने देश का दुश्मन है। हमारा दुश्मन बाद में है। हमारे देश का दुश्मन है, इसलिए हमारा दुश्मन है। यह फैसला अप्रैल में आया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से यह फैसला आया। उन्होंने कहा- जब हमने ऐलान किया। इन लोगों को यह खौफ हुआ। यदि हम इंटरनेशनल कोर्ट गए तो हमारे तमाम फैसलों की छिछालेदर हो जाएगी। हमारी बदनामी हो जाएगी। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुल्क की बदनामी हम नहीं चाहते। मुल्क की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मुल्क के हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मुसलमान से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। इसलिए हम मजबूर थे कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया। यदि यह कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए तो कितने हमने जो बेईमानी के फैसले किए है। सभी पर बात की जाएगी। अजमेर दरगाह के सैयद सरवर चिश्ती बोले- 65 का हो गया हूं, उम्र यदि मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी न कर रहा होता अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा- न हम बटेंगे न हम कटेंगे। एक जन को 20 जने कूट लो तो कर सकते हो, बाकी तो नहीं। 65 साल का हो गया हूं। उम्र यदि मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी न कर रहा होता।

हेट स्पीच पर चिश्ती बोले

उन्होंने अपने बयानों के मामले का जिक्र करते हुए कहा- एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया। मीडिया ट्रायल हुई। मैं हेट स्पीच देता हूं। उनको मोदी की हेट स्पीच नजर नहीं आती। जो हमसे यह कह रहे हैं कि हमें अपनी वेशभूषा से पहचानों। ऐसी बात कभी किसी प्रधानमंत्री ने की। उनके लिए कोई हेट स्पीच नहीं। हमारा कोई शायर कुछ कहे तो उसको जेल में बिठा देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा- मोहब्बत की दुकान ऑनलाइन चल रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा। कनॉट प्लेस और चांदनी चौक में दुकान खोलो। किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं आएगी।

रणथम्भौर से 10 साल में 29 टाइगर गायब

टी-86 बाघ की मौत के बाद जागा वन विभाग, लापता बाघों के रिकॉर्ड खंगालेगी कमेटी

नमस्ते राजस्थान

सवाई माधोपुर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में 3 नवंबर को बाघ टी-86 की हुई मौत के बाद खलबली मची है। लगातार हो रही बाघों की मौत और इनके गायब होने की घटनाओं ने विभागीय अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। 4 नवंबर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने रणथम्भौर से गायब बाघों की जांच को लेकर तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अगले 2 महीने में रिपोर्ट देगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से पिछले 10 साल में 29 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए हैं।

बाघ की हत्या के बाद मची खलबली

कुछ दिन पहले ही रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में टाइगर टी-86 की हत्या का मामला सामने आया था। बारूद से हमला करके टाइगर को मौत के घाट उतारा गया था। इसके अलावा उसकी बॉडी पर चोट के भी निशान थे। इस घटना ने एक बार फिर बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। आला अधिकारियों तक यह मामला पहुंचा और बाघों की कम हो रही संख्या को लेकर जवाब-तलब होने लगा। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगा।

बाघों को ढूंढने के क्या प्रयास हुए, इसकी भी जांच होगी

कमेटी में राजेश कुमार गुप्ता अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अध्यक्ष, उत्र टी. मोहनराज (जयपुर) और मानस सिंह **DFO** (केवलादेव, भरतपुर) को सदस्य नियुक्त किया गया है। अब कमेटी गायब हुए बाघों के रिकॉर्ड की भी जांच करेगी। साथ ही, फील्ड में जाकर हालातों का जायजा लेगी। खास बात यह है कि कमेटी यह भी पता लगाएगी कि गायब बाघों को ढूंढने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों ने आखिर किस तरह के प्रयास किए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलती है तो संबंधित अफसर-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी कमेटी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
फोन नम्बर: 0141-2700151 ई-मेल: pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ( ) निस/मुवजीप्र/2024/ दिनांक

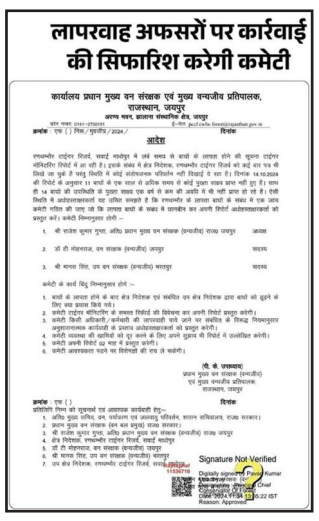

आदेश

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में लंबे समय से बाघों के लापता होने की सूचना टाईगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में आ रही है। इसके संबंध मे क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व को कई बार पत्र भी लिखे जा चुके है परंतु स्थिति में कोई संतोषजनक परिवर्तन नही दिखाई दे रहा है। दिनांक 14.10.2024 की रिपोर्ट के अनुसार 11 बाघों के एक साल से अधिक समय से कोई पुख्ता साक्ष्य प्राप्त नही हुए है। साथ ही 14 बाघो की उपस्थिति के पुख्ता साक्ष्य एक वर्ष से कम की अवधि में भी नहीं प्राप्त हो रहे है। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता यह उचित समझते है कि रणथम्भौर के लापता बाघों के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की जाए जो कि लापता बाघो के संबंध में छानबीन कर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। कमेटी निम्नानुसार होगी –

1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राज० जयपुर — अध्यक्ष
2. डॉ टी मोहनराज, वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर — सदस्य
3. श्री मानस सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर — सदस्य

कमेटी के कार्य बिंदु निम्नानुसार होगें :-

1. बाघों के लापता होने के बाद क्षेत्र निदेशक एवं संबंधित उप क्षेत्र निदेशक द्वारा बाघों को ढूढने के लिए क्या प्रयास किये गये।
2. कमेटी टाईगर मॉनिटरिंग के समस्त रिकॉर्ड की विवेचना कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
3. कमेटी किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।
4. कमेटी व्यवस्था की खामियो को दूर करने के लिए अपने सुझाव भी रिपोर्ट मे उल्लेखित करेगी।
5. कमेटी अपनी रिपोर्ट 02 माह में प्रस्तुत करेगी।
6. कमेटी आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञो की राय ले सकेगी।

(पी. के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अति० मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, शासन सचिवालय, राज० सरकार।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज० सरकार।
3. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राज० जयपुर
4. क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर
5. डॉ टी मोहनराज, वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर
6. श्री मानस सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर
7. उप क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar Upadhyay
Reason: Approved

जल्द रणथंभौर पहुंचेगी कमेटी

कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि सबसे पहले सारे रिकॉर्ड की स्टडी की जा रही है। इसके बाद फील्ड में जाएंगे। टाइगर टैबिटाट के चलते इसे सनसनीखेज नहीं कहा जा सकता है। कमेटी के सदस्य मानस सिंह का कहना है कि अध्यक्ष के निदेर्शानुसार सवाई माधोपुर आकर जांच शुरू की जाएगी।

ट्रैंकुलाइज करते समय ओवरडोज होने से हुई थी बाघ की मौत

साल 2023 के पहले ही महीने में 1 बाघ, 1 बाघिन और 1 शावक की मौत हुई है। 10 जनवरी को बाघ ळ-57, 31 जनवरी को बाघिन ळ-114 और उसके शावक की मौत हो गई थी। इसके अगले महीने में ही 9 फरवरी को बाघिन ळ-19 (कृष्णा) की मौत हो गई थी। मई 2023 में फिर एक टाइगर ने दुनिया छोड़ दी थी। 10 मई को बाघ ळ-104 को ट्रैंकुलाइज करते समय ओवरडोज देने से उदयपुर में उसकी मौत हो गई। सितंबर में फिर बाघिन ळ-79 के दो शावकों की मौत हो गई और बाघिन का पता लगाने में वन विभाग विफल रहा। 11 दिसंबर को बाघिन ळ-69 के शावक की मौत हो गई। इस तरह साल 2023 में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में कुल 8 बाघ-बाघिन और शावकों ने दम तोड़ दिया।

खामियों को दूर करने के दिए जाएंगे सुझाव

कमेटी की ओर से रणथम्भौर की खामियों को दूर करने लिए सुझाव रिपोर्ट में दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर यह कमेटी विशेषज्ञों की राय भी ले सकती है। 15 जनवरी तक जांच रिपोर्ट आने की संभावना है।

प्रसव पीड़ा भी जानलेवा

जनवरी 2024 में 1 बाघिन और 2 शावकों की मौत हो गई। इसी साल जनवरी में बाघिन टी-99 प्री मैच्योर डिलीवरी के चलते गर्भपात का शिकार हुई और उसकी जान चली गई। बाघिन टी-60 व उसके शावक ने प्रसव पीड़ा के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बाद 7 जुलाई 2024 को बाघ टी-58 और 3 नवंबर 2024 को बाघ टी-86 की मौत हो गई थी।

2 साल में 25 बाघ, बाघिन और शावक गायब

रणथम्भौर में पिछले 2 साल में 25 बाघ-बाघिन और शावक गायब हुए हैं। इसको लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके उपाध्याय ने सीसीएफ को कई लेटर लिखे। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद कमेटी का गठन किया गया है।

गायब बाघों को खोजने में वन विभाग नाकाम

रणथम्भौर नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष और वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह कहते हैं- रणथम्भौर में जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुसार बाघों को टेरेटरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बाघों में आपसी संघर्ष बढ़ रहा है। कमजोर बाघ रणथम्भौर से बाहर निकल रहे हैं। कई मर्तबा ताकतवर बाघ से संघर्ष होने पर कमजोर बाघ की मौत भी हो जाती है। विभागीय अधिकारियों की कमजोर मॉनिटरिंग के चलते कई बार मृत बाघों का पता नहीं चल पाता और विभाग उस बाघ को मिसिंग मान लेता है। पथिक लोक सेवा समिति के सचिव व वन्यजीव प्रेमी मुकेश सीट कहते हैं- देखने वाली बात यह होगी कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या देती है। रणथम्भौर के किस-किस अधिकारी पर गाज गिरती है या महज जांच के नाम पर लीपापोती ही की जाती है।

पाली में यात्रियों से भरी बस बनी आग का गोला:

50 से ज्यादा पैसेंजर को बचाया; खिड़कियां तोड़ लगेज फेंका बाहर

नमस्ते राजस्थान

__पाली__ पाली में यात्रियों से भरी चलती अउ स्लीपर बस के इंजन में आग लग गई। ड्राइवर ने बस को बीच रास्ते रोका। यात्री घबरा गए और सामान लेकर उतरने लगे। कुछ देर में आग विकराल हो गई। जब तक दमकल मौके पर पहुंची बस आग का गोला बन चुकी थी।

हादसा रविवार रात 12 बजे जिले के सुमेरपुर थाना इलाके के गांधी चौक में हुआ। बस गुजरात ट्रेवल्स की थी। यह गुजरात से जोधपुर जा रही थी। इस दौरान पाली में हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार पाली जिले के सुमेरपुर थाना इलाके में गांधी चौक के पास रात 12 बजे ड्राइवर को इंजन में आग नजर आई। उसने तुरंत बस को रोका। आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में फायर बिग्रेड को कॉल किया। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों को नीचे उतारा। इंजन में लगी आग बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरी बस में फैल गई। जब तक फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची, आग की लपटों ने पूरी बस को घेर लिया था। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर भंवर देवासी, रूपेश, फायर मैन नरेन्द्र, संदीप, वाहन चालक प्रकाशचंद मावर ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुमेरपुर और शिवगंज से दो फायर बिग्रेड आई थी। अचानक बस में आग लगने से यात्री घबरा गए। कई यात्रियों के साथ बच्चे भी थे जो सो रहे थे। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए तुरंत यात्रियों को बस से निकाल दिया। वरना कुछ देर हो जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से आगे के सफर के लिए भेजने की व्यवस्था की गई।

'मुझे भरोसा दिया-गोल्डी और गोदारा को भारत लाकर गोली मारेंगे' :

गोगामेड़ी की पत्नी बोलीं- 1 साल निकला,गड़बड़ हुई तो करणी सेना अपने हिसाब से चलेगी

नमस्ते राजस्थान

बाड़मेर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने सोमवार को बाड़मेर में कहा- पति के मर्डर केस में चार्जशीट पेश कर दी गई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम हत्याकांड में हैं। उनके कनाडा में होने का अंदेशा है। सरकार और अठकने भरोसा दिलाया था कि दोनों गैंगस्टर को जल्द पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा- हमें भरोसा दिया गया है कि गोल्डी और गोदारा को भारत लगाकर या तो उनका एनकाउंटर कर देंगे या फांसी की सजा देंगे। इस आश्वासन पर एक साल निकाल दिया है। आगे कोई गड़बड़ होती है तो करणी सेना अपने हिसाब से चलेगी। सेना के सदस्य क्या करेंगे यह तो समय बताएगा।

5 दिसंबर को गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) में कार्यक्रम के लिए न्योता दिया

बता दें कि 5 दिसंबर को जयपुर स्थित आवास पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी। उनकी पहली पुण्यतिथि पर पैतृक गांव गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की आदमकद मूर्ति लगाई जाएगी। साथ ही एक स्मारक का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए सर्व समाज को न्योता देने सुखेदव सिंह की पत्नी शीला शेखावत पूरे प्रदेश में घूम रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वे बाड़मेर पहुंचीं थीं। यहां चौहटन रोड पर एक होटल में सुबह 10.30 बजे उन्होंने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन करने के बाद पत्रकारों से बात की।

शीला शेखावत ने बताया...

मूर्ति अनावरण और स्मारक स्थल को लेकर पोस्टर का विमोचन किया है। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होगा। गोगामेड़ी में सुखदेवजी की 8 फीट की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। मैं सर्व समाज के लोगों को आने का न्योता देती हूं।

लॉरेंस के सिर इनाम रखने वालों से हमारा वास्ता नहीं

गैंगस्टर लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखने वालों को लेकर शीला शेखावत ने कहा- किसी की हत्या पर इनाम रखने वालों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। उनका संगठन अलग है। इनाम की घोषणा करना उनका व्यक्तिगत विचार है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लाखों लोग चाहते थे। कोई भाई क्या ऐलान करता है, यह उस पर निर्भर है। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें रास्ता जाम करना पड़े या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। आने वाले समय में हम रणनीति तय करेंगे। बता दें कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने हाल ही सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार 111 रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया था। शेखावत ने कहा था- मुझे सिर्फ इतना पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा का दायित्व हमारा रहेगा।

जयपुर स्थित आवास पर हुई थी गोगामेड़ी की हत्या

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जयपुर स्थित आवास पर 5 दिसंबर 2024 को उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाईं। फिर भाग निकले। गोगामेड़ी को मेट्रो मास हॉस्पिटल (मानसरोवर) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेड़ी के साथ घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में उनको गोगामेड़ी के घर ले जाने वाले युवक की भी मौत हो गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी।

2006 में बनी करणी सेना, फिर अलग होते गए संगठन

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले वे लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे थे। विवाद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अलग संगठन बना लिया था। साल 2006 में सबसे पहले करणी सेना बनी थी। इसके बाद राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने इससे अलग संगठन राजपूत करणी सेना बनाया और साल 2012 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। कुछ समय बाद ही गोगामेड़ी और कालवी में विवाद हो गया। साल 2017 में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अलग संगठन बनाया। वे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आक्रामक अंदाज के कारण वे चचाओं में रहे।

मर्डर के 5 दिन बाद सामने आई थी दूसरी पत्नी

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के 5 दिन बाद एक महिला ने जयपुर में दावा किया कि वह गोगामेड़ी की दूसरी पत्नी सपना सोनी है। एक इंटरव्यू में सपना ने कहा- गोगामेड़ी के एक नहीं, तीन पत्नियां हैं। तीनों से गोगामेड़ी ने समाज-परिवार के सामने फेरे लेकर शादी नहीं की। तीनों ने अपनी मर्जी से गोगामेड़ी के साथ रहना स्वीकार किया। तीनों के आपस में नहीं बनने के कारण वे अलग-अलग रहती हैं। दावा किया कि गोगामेड़ी की पहली पत्नी शकुंतला चौधरी, दूसरी वह स्वयं (सपना सोनी) और तीसरी पत्नी शीला कंवर (शीला शेखावत) है। सपना ने कहा था- शीला राजपूत समाज से है, इसलिए उसका सपोर्ट किया जा रहा है।

महिला की संदिग्ध हालत में मौत:

पीपानंद पैनोरमा के पास मिली थी बेहोश, मानसिक हालत नहीं थी ठीक

नमस्ते राजस्थान

झालावाड़ झालावाड़ के गागरोन रोड पर पीपानंद पैनोरमा के पास एक महिला की संदिग्ध हालत में मिली। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि शहर के खंडिया कॉलोनी इलाके में रहने वाली महिला को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस से झालावाड़ जिला अस्पताल लेकर आए। यहां इलाज के दौरान रविवार शाम को मौत हो गई। पुलिस ने शव को मॉर्चुरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। इस पर परिजन जिला अस्पताल आए। महिला के बेटे ने बताया कि वह घर से सुबह काम पर चला गया था। दोपहर में सूचना मिली कि उसकी मां बेहोश पड़ी हुई है। इस पर एम्बुलेंस से झालावाड़ अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने बेटे की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। महिला की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी।

गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ा सांड,

दो सांडों की लड़ाई के दौरान बचने के लिए चढ़ा, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा

धौलपुर रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास रविवार शाम को 2 सांड अचानक बीच सड़क पर लड़ पड़े। इस दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सीढ़ियों से होते हुए गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ गया, जिससे गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया। सांड को छत पर चढ़ा हुआ देखकर तमाशबीन लोगों की भीड़ जुट गई। दो सांडों के बीच हो रही लड़ाई के दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सड़क पर बनी सीढ़ियों के सहारे गेस्ट हाउस की छत के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद गेस्ट हाउस संचालकों ने नगर परिषद को सूचना दी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नगर परिषद की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जिस पर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने ही आपसी सहयोग से रस्सा और डंडों की सहायता से सांड को नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद सांड आक्रोशित हो गया और उसने तांडव मचा दिया, जिससे कुछ लोगों के चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीच सड़क पर आवारा पशुओं की लड़ाई की वजह से कई घंटे तक जाम भी लगा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा पशुओं के लिए नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। टो 16

पदमपुर रोड बाईपास पर हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार:3 पिस्टल बरामद

नमस्ते राजस्थान

श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर में पदमपुर रोड बाईपास पर राधास्वामी डेरे के सामने एक युवक को 3 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। रविवार को यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने रविवार को एक युवक को पदमपुर रोड बाईपास पर राधास्वामी डेरे के सामने 3 पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। युवक यह पिस्तौल अपने पास रखे हुए यहां खड़ा था। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की। घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रोका। वहीं मौके पर डीएसटी इंचार्ज एसआई रामविलास भी पहुंच गए। आरोपी घबरा गया तो उसे रोककर तलाशी ली। इस पर उसके पास 3 पिस्तौल बरामद हुए। पुलिस ने पिस्तौल कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील कुमार उर्फ देवराज पुत्र पन्नालाल लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के गांव 23 एलएनपी लाधूवाला का रहने वाला है। उसके पास मिले 3 पिस्टल में दो 32 बोर और एक 30 बोर का है। वह इससे पहले एनडीपीएस के मामलों में पकड़ा जा चुका है। वह इससे पहले एनडीपीएस के मामले में जेल में भी रह चुका है। उसने ये पिस्टल मध्यप्रदेश से खरीदे थे। वह इससे पहले भी मध्यप्रदेश से श्रीगंगानगर लाकर श्रीगंगानगर और पंजाब के आसपास के इलाकों में हथियार बेच चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

अजमेर में बेटी के ससुराल में की चोरी:पिता-पुत्र गिरफ्तार, 24 लाख रुपए के जेवरात बरामद-पूछताछ जारी

नमस्ते राजस्थान

अजमेर अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने महीने भर पहले एक मकान में हुई लाखों के जेवरात और नकदी चोरी के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी के ससुराल में वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मामले का पदार्फाश करने के साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चुराया गया 24 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। गौसिया कॉलोनी, बड़े पीर रोड निवासी मुजफर भारती पुत्र सरदार-अली के मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हो गए थे। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 अक्टूबर को उसका परिवार एक रिश्तेदार के यहां दावत में गया था। इस दौरान कमरे की कुंडी को काटकर घुसे चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने की 3 चेन, 5 पेंडिल, 2 हथफूल, सोने की 15 छोटी बड़ी अंगूठियां और 3 लाख 50 हजार रुपए चुरा लिए। चोरों ने छत पर बने कमरे का भी ताला तोड़ न दिया और वहां से 4 तोला सोने की 5 अंगूठियां, एक सोने का 7.5 ग्राम का पेंडिल, 1 सोने का झुमका, 1 मोतीमाल सोने की, 2 चांदी की चेन भी समेट कर ले गए।

100 CCTV कैमरे खंगाले, तब मिला सुराग

दरगाह थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आसपास के 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। साइबर टीम ने सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का डेटा कलेक्ट कर संदिग्ध व्यक्तियों को चिह्नित किया। कैमरे की फुटेज में दिखाई दिए अंदरकोट ढाई दिन का झोपड़ा हाल किरायेदार गरीब नवाज कॉलोनी नई सड़क निवासी सीम हुसैन (45) पुत्र अफजल हुसैन और उसके पुत्र शहान (22) को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहान अपनी बहन के घर आता जाता रहता था। रिश्तेदारी और जान पहचान का फायदा उठा कर परिवार जब अंदरकोट में अपने रिश्तेदार के यहां दावत में गया हुआ था, तब पिता के साथ मिलकर चोरी की वारदात अंजाम दी।

जयपुर में 24 घंटे से पानी की टंकी पर युवक:

रकभर्ती रद्द करने की मांग पर अड़े, बोले- सरकार अपने मंत्री-अफसर के दबाव में

नमस्ते राजस्थान

जयपुर रकभर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक टंकी पर चढ़े हैं। रविवार को दोपहर 1 बजे टंकी पर चढ़े युवक अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं। पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। दोनों युवकों ने कहा- हमारे कुछ साथियों को उट भजनलाल शर्मा से मिलवाया जाए। इसके बाद उट लेटर जारी कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करें। इसके बाद ही वो टंकी पर से उतरेंगे। उधर, दोनों युवकों ने कहा कि सरकार अपने मंत्री और अफसर के दबाव में है। इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है।

रविवार दिन में टंकी पर चढ़े थे दोनों युवक

रविवार (10 नवंबर) दोपहर करीब 1 बजे लादूराम चौधरी (35) और विकास विधूड़ी (34) हिम्मत नगर स्थित पानी की टंकी पर 2 बैनर लेकर चढ़ गए थे। युवकों ने बैनर पर रक पेपर लीक को लेकर 7 पॉइंट में अपनी मांगें लिखी हैं। इसमें लिखा है- आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं? ध्यानाकर्षण सत्याग्रह। भजनलाल सरकार से छात्रों का आह्वान, एसआई भर्ती रद्द करो, लीपापोती बंद करो। आखिर फिर से बड़ा सवाल सरकार इस एसआई भर्ती परीक्षा पर कब फैसला करेगी...कब-कब और आखिर कब? दोनों बैनर को लादूराम और विकास ने टंकी पर ही टांग दिया।

इसकी सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। दोनों युवकों से बात की, लेकिन उन्होंने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौतम, एसीपी मालवीय नगर, सीआई बजाज नगर, सीआई जवाहर सर्किल मौके पर दोनों युवकों से बात की, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है।

30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम:

आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराएगा; 11 साल में दूसरी बार पैरोल मिली

जोधपुर रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। उसे 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पैरोल मिली है। इससे पहले उसे अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी।

अनिश्चितकालीन छुट्टी मांगी थी

आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए इलाज की अनुमति के लिए आवेदन पेश किया था। आसाराम के वकीलों ने जब तक अस्पताल से डॉक्टर छुट्?टी नहीं दे देता, तब तक अनिश्चितकालीन अवधि तक इलाज की अनुमति मांगी थी। सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने 30 दिन की अनुमति की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आसाराम को 30 दिन इलाज के लिए पैरोल दी। इससे पहले 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी थी। वह इलाज के लिए 11 वर्ष में पहली बार पैरोल पर आया था। तब आसाराम ने महाराष्ट्र के माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाया था। उसके बाद आसाराम को फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया था।

महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 'पद्मावत' मूवी का किया था विरोध:

गुलाबचंद कटारिया के साथ निकाली थी पैदल यात्रा;सादगी के कायल थे लोग

नमस्ते राजस्थान

उदयपुर उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ (83) का रविवार को निधन हो गया। वे राजपरिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। उनसे मिलने आने वाले लोग उनकी इस सादगी के कायल हो जाते थे। यही नहीं, महेंद्र सिंह मेवाड़ अपनी बातें खुलकर कहते थे। संजय लीला भंसाली निर्देशित बॉलीवुड फिल्म 'पद्मावत' का तथ्यो से तोड़-मरोड़ करने के कारण उन्होंने खुलकर विरोध किया था। सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए थे।

फिल्म 'पद्मावत' का किया था विरोध

जनवरी 2018 में 'पद्मावत' मूवी को लेकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने फिल्म का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म में जो बताया गया है, वह न तो इतिहास में है और न ही मलिक मोहम्मद जायसी लिखित पद्मावत में है। उन्होंने तब सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए थे। तब मेवाड़ ने कहा था कि इतिहास की खिल्ली क्यों उड़ाई जा रही है।

कटारिया ने मेवाड़ के साथ निकाली थी पैदल यात्रा

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कहते हैं- मैंने उनको राजनीति में जोड़ने के लिए पहला प्रयास किया था। वह भी उस समय जब एक तरह से पार्टी (बीजेपी) को खड़ा करना कठिन काम था। तब एकलिंगजी मंदिर से उदयपुर शहर तक हमने 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा साथ की थी। उसके समापन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। उसके बाद से मेरा उनसे लगातार संपर्क बना रहा। तब वे चित्तौड़गढ़ से और मैं उदयपुर लोकसभा सीट से जीतकर संसद गया था। एक तरह से राजनीति में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। कई बार उनके घर जाना होता था। पिछले दिनों उनसे अस्पताल में भी मिलकर आया था। उनका जाना मेवाड़ के लिए भी बड़ी क्षति है।

2007 में आचार्य महाप्रज्ञ का लिया था आशीर्वाद

उदयपुर में साल 2007 में आचार्य महाप्रज्ञ का चातुर्मास था। तब उदयपुर के फील्ड क्लब में आचार्य महाप्रज्ञ के स्वागत के लिए महेंद्र सिंह मेवाड़ पहुंचे थे। भाजपा नेता और जैन समाज के प्रमोद सामर बताते हैं कि तब आचार्य से महेंद्र सिंह मेवाड़ ने आशीर्वाद लिया और चर्चा की।

इंटरव्यू करने गए तो सफेद हाफ पैंट और टीशर्ट में थे

राजस्थान के साहित्यकार डॉ. महेंद्र भानावत बताते हैं- एक बार मैं महेंद्र सिंह मेवाड़ का इंटरव्यू करने समोर बाग गया था। दरवाजे पर बेल बजाई तो एक व्यक्ति दरवाजा खोलने आया। वे बोले- 'पधारो सा, बिराजो।'
उस व्यक्ति ने सफेद हाफ-पैंट और टी-शर्ट पहन रखी थी। वे हमें बैठाकर अंदर चले गए। फिर कपडे. बदलकर आए और बोले- हां साहब। वे महेंद्र सिंह मेवाड़ ही थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सादगी से रहते हैं। उस समय न हमने उनसे कुछ पूछा और न कुछ कहा। हमने सोचा कि कितने सीधे और सादगी पूर्ण व्यक्ति हैं। डॉ. भानावत कहते हैं- निधन का समाचार सुना तो दुःख हुआ। उनका सीधा-साधा व्यक्तित्व था।

मेवाड़ी के साथ-साथ अंग्रेजी में महारत थी

मेवाड़ जन उदयपुर संस्था के संयोजक कंवर प्रताप सिंह झाला 'तलावदा' बताते हैं- महेंद्र सिंह मेवाड़ ने बचपन से लेकर जीवन पर्यंत सादगी पूर्ण जीवन शैली, स्व-अनुशासन, शिष्टाचार के साथ लोक मयार्दाओं का पालन करते हुए अपना जीवन बिताया। ज्ञान और व्यवहार के दृष्टिकोण से मेवाड़ बोलचाल की भाषा और लेखन को लेकर बहुत सतर्क थे। वे कहते हैं- मेवाड़ तुच्छ और अपमानजनक भाषा से हमेशा परहेज करते थे। लेखन और बोलचाल की दृष्टि से मेवाड़ को उच्च कोटि की अंग्रेजी भाषा व मेवाड़ी भाषा में महारत हासिल थी।

एकलिंगजी पर लिखी पुस्तक का विमोचन मेवाड़ से कराना था

इतिहासकार डॉ. जी.एल. मेनारिया ने बताया- उन्होंने और डॉ. अजात शत्रु सिंह शिवरती ने मेवाड़नाथ भगवान श्रीएकलिंगजी पर पुस्तक लिखी और इसका विमोचन महेंद्र सिंह मेवाड़ से कराने का मन था। उनकी तबीयत खराब होने से नहीं हो पाया था। मेनारिया बताते हैं- वे पुस्तक को लेकर बातचीत करने भी समोर बाग गए थे। तब मेवाड़ और उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात हुई थी। डॉ. मेनारिया बताते हैं कि अभी तक उन्होंने पुस्तक का विमोचन नहीं कराया है।

---

42 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी स्टूडेंट गिरफ्तार:

200 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया, फर्जी इन्वेस्टमेंट करवा कर मुनाफे का लालच देता था

अजमेर फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 महिलाओं से 42 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक स्टूडेंट को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टूडेंट मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने बताया कि नसीराबाद निवासी पीड़ित महिला उषा राठौड़ वह माला पथरिया ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। जिसमें शिकायत देकर बताया कि आरोपियों ने फर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए लगवाकर कम समय में अधिक मुनाफे का लालच का झांसा देकर 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

आरोपी को किया गिरफ्तार

सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने बताया कि टीम ने जांच करते हुए नसीराबाद निवासी कासिफ मिर्जा (19) पुत्र परवेज मिर्जा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा इंस्टाग्राम आईडी व व्हाट्सएप पर प्रचार प्रसार कर इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कीम चला कर धोखाधड़ी की जाती थी। आरोपी वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नवंबर 2023 से ही उसने इस तरह से धोखाधड़ी करना शुरू किया था।

---

50 तोला सोना चोरी, 15 दिन बाद 35 तोला मिला:

तंत्र-मंत्र का डर दिखाया तो वापस फेंक गए चोर;डळर में महिला ऑफिसर के घर में वारदात

नमस्ते राजस्थान

जयपुर जयपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओटीएस) में पब्लिकेशन ऑफिसर के घर से 50 तोला सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई। पीड़ित ने जब संदिग्धों को तंत्र-मंत्र का डर दिखाया तो 15 दिन बाद 35 तोला सोने के जेवर पर्स में डालकर घर के पीछे लॉन में फेंक गए। दरअसल, पब्लिकेशन ऑफिसर डॉ. अमृत कौर 25 अक्टूबर को घर से बाहर गई हुई थीं। दोपहर एक बजे जब वह घर लौटीं, तो अंदर अलमारी का सामान बिखरा पड़ा मिला। महिला अधिकारी ने चेक किया तो पता चला कि अलमारी में रखी 50 तोला सोने की ज्वेलरी और करीब 50 हजार रुपए नकद चोरी हो चुके हैं। उन्होंने गांधी नगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों की तलाश में जुटी। शक के आधार पर पुलिस ने ओटीएस में सफाई करने वाले 3 लोगों को डिटेन किया और शनिवार (9 नवंबर) को थाने लेकर आई। इसी दौरान अमृत कौर भी थाने पहुंचीं। उन्होंने चोरों को डराने के लिए कह दिया है कि वह तंत्र-मंत्र से जान चुकी है कि चोर कौन है। उसका चेहरा वह जानती है। इससे डिटेन किए हुए तीनों लोग काफी डर गए। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन रविवार (10 नवंबर) को सुबह अमृत कौर को उनके गार्डन में एक पर्स मिला। पर्स में 35 तोला सोने की ज्वेलरी थी।

दरवाजे की जाली को अंदर से काटकर की थी चोरी

तीनों संदिग्धों से फिर होगी पूछताछ

गांधीनगर सीआई राजकुमार ने बताया- शनिवार को सफाई कर्मचारियों से रात 10 बजे तक पूछताछ की। इसके बाद रविवार सुबह 9 बजे लॉन में पर्स मिला, जिसमें करीब 35 तोला सोने के जेवर थे। इसकी सूचना अमृत कौर ने दी तो गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सामान चेक किया तो पर्स में सोने की 2 चेन, 2 मंगल सूत्र, रखड़ी, सोने की 6 अंगूठी, डायमंड सेट, सोने की चूड़ियां, टॉप्स, गले का हार और चांदी के कड़े मिल गए। इन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। शनिवार को जिन तीनों सफाई कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी, अब उनसे दोबारा पूछताछ होगी।

चोरी का रूप देने के लिए दरवाजे की जाली को काट दिया

पब्लिकेशन ऑफिसर अमृत कौर का कहना है कि घर के मेन गेट को चाबी से खोला गया था। उसकी चाबियां उनकी स्टाफ की ही परिचित को दी हुई थी। जब 25 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे घर पहुंची तो घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ मिला। दरवाजे पर लगी जाली को काटा हुआ था। अलमारी में सामान बिखरा था। इसके बाद जब पता किया तो पाया कि दरवाजे की जाली को अंदर से काटा गया था। शक गहरा गया कि चोर परिचित है और उसने प्लानिंग बनाकर चोरी की है। अमृत कौर जानती थी कि चोर कौन है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। जिस पर पुलिस को केस की जानकारी दी थी।

स्टाफ क्वार्टर में रहती हैं महिला अधिकारी

अमृत कौर को ओटीएस कैंपस में स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ है। जहां वे पति और बच्चे के साथ रहती हैं। जब चोरी की वारदात हुई, तब वे अपने परिवार के साथ घर गई हुई थीं। डिटेन किए गए तीनों सफाई कर्मचारी ओटीएस में ही अलग-अलग जगह पर सफाई का काम करते हैं। ये तीनों ही ठेकेदार के कर्मचारी हैं।

अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

नमस्ते राजस्थान

भीलवाडा, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध) को शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराए जा रहे है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई., शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऋण आवेदन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार), गारंटर संबंधित और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है, साथ ही शिक्षा ऋण के लिए समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन/मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि ऑनलाईन आवेदन के दौरान अपलोड होना अतिआवश्यक है। इस प्रकार व्यवसाय ऋण के लिए आवेदक की आयु 18-54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदक की आयु 16-32 वर्ष होनी चाहिए। समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर अंतिम तिथि 30 नवंबर से पूर्व तक ऋण आवेदन वेबसाइट/लिंक ”https://milÔffmdfc.org” पर ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हे। ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01482-232086 पर सम्पर्क कर सकते है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

रेड फ्लेग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों के संबंधित विद्यार्थी वांछित दस्तावेज 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करें

नमस्ते राजस्थान

भीलवाडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में रेड फ्लेग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों हेतु अनेक बार रेड फ्लैग सत्यापन हेतु विद्यार्थियों को मैसेज करवाने के उपरान्त भी विद्यार्थी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर रेड फ्लैग का सत्यापन नही करवा रहे है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम अवसर प्रदान कर शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में रेड फ्लैग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों के संबंधित विद्यार्थी को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 30 नवम्बर तक तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात इस शैक्षणिक सत्र के रेड फ्लैग में प्रदर्शित आवेदन पत्रों को स्थाई रूप से निदेशालय द्वारा निरस्त कर दिये जायेगें तथा ऐसे आवेदन पत्रों पर भविष्य में कोई विचार नही किया जायेगा।

अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का संचालन प्रारम्भ कर अन्तिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र छात्र द्वारा एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम जनाधार कार्ड द्वारा ZU¯°fSXZQ¯WXUA¯fQ ए व fYfOX`¯°fÔSXZþeQ¯WXUA¯´fQ पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तें सामान्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट ेजिजचरूध्ध्ेरमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद पर उपलब्ध हैं।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 12 नवंबर को

नमस्ते राजस्थान

भीलवाडा, जिला सड़क सुरक्षा समिति की माह नवम्बर की बैठक 12 नवंबर को दोपहर 12.00 बजे (साप्ताहिक बैठक के साथ) जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित होगी। यह जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने दी।

मुसलमान राजनीति में दाढ़ी रखकर आता है तो आपत्ति नहीं:

पूर्व सांसद सुमेधानंद बोले,खड़गे कितने सारे संतों को राजनीति में लेकर आए और लाभ उठाया

नमस्ते राजस्थान

सीकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संतों को लेकर दिए बयान पर सीकर के पूर्व भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। पूर्व सांसद ने कहा- कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, बीजेपी संतों के कपड़े बदल दें। पूर्व संसार ने मीडिया बयान जारी किया है। सुमेधानंद ने बोला- मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांककर देखिए और कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। देश की आजादी के लिए कितने सारे संत जेल में गए। यदि एक-एक का नाम गिनाया जाए तो उनकी संख्या सैकड़ों हो जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में सैंकड़ों सन्यासियों ने देश की आजादी के लिए काम किया है। पूर्व सांसद ने कहा- मुसलमान राजनीति में दाढ़ी रखकर आता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। कितने सारे संतों को यह स्वयं राजनीति में लेकर आए और उनका लाभ उठाया। आज भाजपा में साधु,संत,सन्यासी राजनीति करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखें और इस प्रकार की आपत्ति करना बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर सोचें और खेद व्यक्त करें। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि कई नेता साधु के भेष में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं। कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं हैं। उनके मुखिया बीजेपी से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहनें या अगर आप संन्यासी हैं या गेरूआ कपड़े पहनते हैं। तो राजनीति से बाहर हो जाएं।

युवक को चोर समझा, पीट-पीटकर मार डाला:

बंधक बनाकर बेहोश होने तक पीटते रहे; पुलिस पहुंची तो घर के बाहर पड़ा मिला शव

नमस्ते राजस्थान

बारां बारां में एक युवक को लोगों ने चोर समझ लिया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। युवक खेत में बने एक घर में घुस गया था। इस दौरान परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया और बेहोश होकर गिरने तक पिटाई की। युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक घर के बाहर पड़ा था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला सदर थाना इलाके के बरानी गांव का है। घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा था युवक डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- बरानी गांव में शनिवार देर रात एक युवक खेत में बने घर में घुस गया था। परिवार के लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। युवक के बेहोश होकर गिरने तक उसको पीटते रहे। डीएसपी ने बताया- सदर थाना पुलिस को रात करीब 3 बजे युवक को बंधक बनाकर पिटाई करने की सूचना मिली थी। इस पर टीम बरानी गांव पहुंची। यहां एक खेत में बने मकान के बाहर युवक गंभीर हालत में पड़ा था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए सबूत

उन्होंने बताया- पुलिस ने रविवार सुबह घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सबूत जुटाए। पुलिस ने युवक की पहचान के प्रयास किए तो उसकी पहचान नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हरिपुरा निवासी श्यामलाल उर्फ देवकिशन (25) पुत्र गोरधनलाल ओढ के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बरानी निवासी महावीर के खिलाफ युवक से मारपीट कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

E-Mail: namasterajasthan11@gmail.com, nrnews100@gmail.com

चीन से जंग में हार का दोषी नेहरू जी को क्यों न माना जाए?

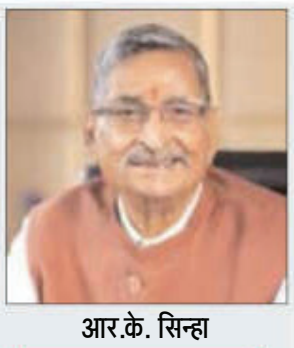

आर.के. सिन्हा

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल चीन के साथ संबंधों में सदैव उतार-चढ़ाव का ही बना रहा। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से लेकर 1964 में मृत्यु तक, नेहरू का दृष्टिकोण चीन के प्रति विश्वास और आकर्षण से शुरू होकर अंततः चरम उदासीनता में बदल गया था। चीन से स्पष्ट नकारात्मक संकेतों के बावजूद, नेहरू ' हिंदी - चीनी भाई-भाई ' का नारा बुलंद कर न जाने क्यों संबंध के भ्रम को बनाए रखने के लिए ही उत्सुक थे।

भारत और चीन के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इससे या आशा की जाती है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने में मदद मिलेगी। दशकों बाद यह एक सकारात्मक पहल हुई है। सबको पता है कि दोनों मुल्कों के सीमा विवाद के कारण ही 1962 में जंग भी हुई थी। उस जंग में भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीन के गले में अंगूठा तो डाल दिया था, पर चीन ने हमारे बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। चीन के खिलाफ जंग में भारत के उन्नीस रहने के लिए कौन मुख्य रूप से दोषी था? कांग्रेस नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह कहते थे कि चीन नीति पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि की कमी थी। इसी कारण 1962 में भारत की सेना चीन से हारी थी। उस जंग के समय नटवर सिंह भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ ज़िम्मेदार अफसर थे। वे कहते थे, 'जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हम चीन के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। वे समझ ही नहीं सके कि चीन हमारी पीठ पर छुरा घोंप देगा। दुर्भाग्यवश, उनकी चीन नीति बुरी तरह से गलत साबित हुई।' यह लिखा है पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने जो कांग्रेस सरकार में ही मंत्री थे।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल चीन के साथ संबंधों में सदैव उतार-चढ़ाव का ही बना रहा। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना से लेकर 1964 में मृत्यु तक, नेहरू का दृष्टिकोण चीन के प्रति विश्वास और आकर्षण से शुरू होकर अंततः चरम उदासीनता में बदल गया था। चीन से स्पष्ट नकारात्मक संकेतों के बावजूद, नेहरू ' हिंदी - चीनी भाई-भाई ' का नारा बुलंद कर न जाने क्यों संबंध के भ्रम को बनाए रखने के लिए ही उत्सुक थे। वे देश को चीन से जुड़े विवाद को लगातार छिपाते रहे और कृष्णमेनन जैसे कम्युनिस्ट की बात मानकर लगातार देश विरोधी गलत निर्णय लेते रहे।

दरअसल नेहरू के साथ एक बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्हें लगता था कि सारा बुद्धि- विवेक और समझदारी उन्हीं के पास है। चीन से युद्ध के बाद उनके जन्म दिन (14 नवंबर) को संसद में चीन से युद्ध के परिणामों पर हो रही चर्चा पर

उन्हें बोलना था। चर्चा 8 नवंबर, 1962 से ही जारी थी। सभी दलों के नेता अपनी बेबाक राय रख रहे थे। संसद के बाहर भी नेहरू को ही घेरा जा रहा था। लोहिया ने 1949 में ही देश को आगाह कर दिया था कि उत्तरवर्ती सीमाओं से देश पर साम्यवाद का खतरा मंडरा रहा है। यह बात उन्होंने खासतौर पर तिब्बत, नेपाल और सिक्किम में चीन की भूमिका को लक्ष्य करते हुए कही थी। साल 1950 में तिब्बत पर चीन के हमले की निंदा करने वालों में डॉ ० लोहिया अग्रणी रहे। इसके बाद से उन्होंने लगातार चीन की सीमा पर नजर जमाये रखी और नेहरू को खबरदार किया कि चीनी निजाम को उसकी कथनी के हिसाब से देखना-समझना या फिर चीन के साथ सीमाओं को लेकर किसी किस्म के लेन-देन की बातचीत में उतरना ठीक नहीं। साल 1962 में भारत को जो सदमा झेलना पड़ा उसके लिए लोहिया ने नेहरू को बड़ी खरी-खरी सुनायी थी। खैर, नेहरू ने संसद में लंबी बहस के बाद अपना वक्तव्य देना शुरू करते हुए कहा- 'मुझे दुख और हैरानी होती है कि अपने को विस्तारवादी शक्तियों से लड़ने का दावा करने वाला चीन खुद विस्तारवादी ताकतों के नक्शेकदम पर चलने लगा।' उन्हें सारा सदन पूरी गंभीरता से सुन रहा था। नेहरू जी बता रहे थे कि चीन ने किस तरह से भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। पर जब उनके भाषण के बीच किसी सदस्य ने हस्तक्षेप किया तो वे बुरी तरह नाराज हो गए। पहली बार करनाल से सांसद स्वामी रामेश्वरानन्द ने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, 'चलो अब तो आपको भी चीन का असली चेहरा दिखने लगा। ' इस टिप्पणी पर नेहरू नाराज हो गए। कहने लगे, 'अगर माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें सरहद पर भेजा जा सकता है।' सदन को भी नेहरू की यह बात समझ नहीं आई। नेहरू प्रस्ताव पर बोलते ही जा रहे थे। तब एक और सदस्य एच.वी.कामथ ने कहा, 'आप बोलते रहिए। हम बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे।'

अब नेहरू विस्तार से बताने लगे कि चीन ने भारत पर हमला करने से पहले कितनी तैयारी की हुई थी। इसी बीच, स्वामी रामेश्वरानंद ने फिर तेज आवाज में कहा, 'मैं तो यह जानने में उत्सुक हूं कि जब चीन तैयारी कर रहा था, तब आप क्या कर रहे थे?' अब नेहरू अपना आपा खो बैठे और कहने लगे, 'मुझे लगता है कि स्वामी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अफसोस है कि सदन में इतने सारे सदस्यों को रक्षा मामलों की पर्याप्त समझ नहीं है।' वे सदन में अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे थे। निश्चित रूप से चीन से जंग के कारण वे हताश थे। उन्हें उस जंग की परिणाम ने गहरी चोट पहुंचाई थी। इसलिए वे सदस्यों पर बरसने लगते थे।

बहरहाल, चीन के खिलाफ जंग के 62 साल गुजरने के बाद भी देश उस युद्ध में जो कुछ हुआ, उसे भुला नहीं पाया है। हालांकि तब से की कई पीढ़ियां पैदा हुईं और जवान हो गईं। राजधानी दिल्ली में अनेक सड़कों के नाम जंग में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के नामों पर हैं। पर साउथ दिल्ली की ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पहली सड़क थी जो किसी रणभूमि के योद्धा के नाम पर रखी गई थी। यह बात 1963 की है। चीन के साथ हुई जंग के बाद पहले जिस सड़क को लक्ष्मी बाई नगर मार्ग कहा जाता था, वो हो गई ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग। ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने चीन के खिलाफ 1962 में हुई भीषण जंग में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वे भारतीय सेना की टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे। कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़े न होने और युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रों के अभाव को उन्होंने आड़े आने नहीं दिया था। उस समय रणभूमि में ब्रिगेडियर होशियार सिंह की शौर्य गाथासुनकर सारे देश में देशभक्ति की भावना पैदा हो गई थी। इसलिए उस युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद राजधानी की एक खास सड़क का नाम उस महान वीर के नाम पर रख दिया गया। होशियार सिंह मार्ग का नामकरण करने के लिए देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण खुद आए थे। यानी देश ने अपने उस महान शूरवीर की याद में एक कृतज्ञता का भाव प्रकट किया था। अब भी ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग से गुजरते हुए उस महान शूरवीर और 1962 की जंग के यादें ताजा होने लगती हैं।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

संपादकीय

बिला वजह विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान से वंचित करने वाले 1967 के अजीज बाशा केस को पलटते हुए अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का मसला रेग्युलर बेंच को दे दिया। अदालत ने कहा कि कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 के अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था जिसके खिलाफ सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इसे सात जजों की पीठ को भेज दिया था। बीती फरवरी में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 1967 में अजीज बाशा बनाम भारत गणराज्य मामले में शीर्ष अदालत ने भी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया था। कहा कि कानून के मुताबिक स्थापित संस्थान अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता पर 1981 में सरकार ने एएमयू एक्ट में संसोधन कर विवि का यह दर्जा बरकरार कर दिया। एएमयू को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है। आजादी की क्रांति का हिस्सा रहे सर सैय्यद अहमद खान ने इसके गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। समान शिक्षा के मामले में पिछड़ते मुसलमानों की स्थिति सुधारने की मंशा से उन्होंने तमाम तरक्की पसंद मुसलमानों के साथ मिल कर इस विवि की नींव ड़ाली थी। उनका सपना था कि देश के मुसलमान उच्च शिक्षा हासिल कर प्रतिष्ठित पदों कर काबिज हों। एएमयू में फिलवक्त सैंतीस हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं जिन्हें बगैर किसी जाति, पंथ, संप्रदाय या लिंग के भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जा रही है। हालांकि कुछ पाठ्यक्रम सार्क और राष्ट्रमंड़ल देशों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। धार्मिक आधार पर देशवासियों को बांटने की राजनीति करने वालों के लिए यह करारा झटका हो सकता है जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लालयित युवाओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण देने के प्रयास होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक विवादों से परे रखना चाहिए। सवाल अल्पंख्यक शिक्षण संस्थान का नहीं है, बल्कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का होना चाहिए जिसमें हमारे विश्वविद्यालय बुरी तरह से असफल हैं। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में फिसड्डी साबित होने के बावजूद हमारा ध्यान उधर नहीं है जो छात्रों के बेहतरीन भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।

चिंतन-मनन

मनोबल कम न हो

जीवन की जितनी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, वे वास्तविक समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं हमारी काल्पनिक भी हैं। काल्पनिक समस्याएं भी कम भयंकर नहीं होती। वास्तविक समस्याएं बहुत थोड़ी हैं, गिनी-चुनी। किन्तु काल्पनिक समस्याओं का कहीं अंत नहीं है। इतनी जटिल समस्याएं जो प्रतिदिन हमारे सामने उभरती हैं। किस प्रकार काल्पनिक समस्याएं मनुष्य को सताती हैं, इसका एक उदाहरण है-

दो यात्री आमने-सामने ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन में लड़ाई हो गई। लड़ाई का कारण, एक समस्या। समस्या काल्पनिक, केवल काल्पनिक। एक कहता है मुझे ठंड लग रही है और दूसरा कहता है मुझे गर्मी लग रही है। एक उठता है, खिड़की को बंद कर देता है। दूसरा उठता है खिड़की को खोल देता है। टी.टी. आया, यह अभिनय देखा और बोला, क्या तमाशा हो रहा है रेल में! चलती गाड़ी में क्या खेल खेला जा रहा है! एक ने कहा, हवा बहुत तेज चल रही है, मुझे ठंड लग रही है। दूसरा कहता है, खिड़की बन्द हो जाती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, परेशान हो रहा हूं। टी.टी. गया खिड़की के पास और जाकर देखा तो खिड़की का प्रेम तो है, लेकिन शीशा है ही नहीं। अब कैसे हवा लग रही है और कैसे गर्मी लग रही है? मात्र काल्पनिक समस्या।

हमारी दोनों प्रकार की समस्याएं हैं-काल्पनिक समस्याएं और यथार्थ समस्याएं। ये हमारे मनोबल को कमजोर करती हैं। जिस व्यक्ति का मनोबल कम होता है, वह व्यक्ति इस दुनिया में अपराधी का जीवन जीता है। दुर्बलता खुद एक अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट के 51वें, मोदी सरकार के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना

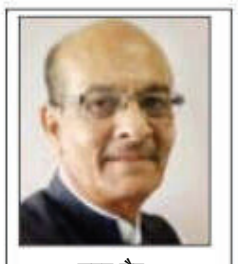

सनत जैन

सुप्रीम कोर्ट के 51 वे मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने आज शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार के आने के बाद संजीव खन्ना दसवें मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी। संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस देवराज खन्ना के सुपुत्र और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना के भतीजे हैं। खन्ना परिवार के वह एक ऐसे सदस्य हैं जो न्यायपालिका के सबसे उच्च पद पर पहुंचे हैं। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल किस तरह का होगा, इसको लेकर अभी से धारणा बनना शुरू हो गई है। पिछले 10 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली की सबसे ज्यादा चचाएं हुई हैं। संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं। गुण दोष के आधार पर न्यायपालिका का फैसला अंतिम माना जाता है। 2014 के पहले संविधान में प्रदत मौलिक अधिकारों को लेकर न्यायपालिका सजगता के साथ संविधान के अनुसार गुण दोष के आधार पर निर्णय करती थी। न्यायपालिका ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं दिया। न्यायपालिका के पास जो भी मामले गए। निष्पक्षता के साथ दोनों पक्षों को सुनते हुए संविधान के अनुरूप फैसला देने में कभी कोई कोताही न्यायपालिका ने नहीं की। जिसके कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आम जनमानस का हमेशा विश्वास बना रहा। न्यायपालिका ने अपना अंकुश सही मायने पर सरकार और कार्यपालिका पर रखा। इन्हीं के पास अधिकार होते हैं। अधिकारों के बल पर सरकार और कार्यपालिका निरंकुस होती हैं। इनके लिए अंकुश की जरूरत पड़ती है। सरकार जो भी कानून और नियम बनाती है। वह संविधान के अनुरूप हैं, या नहीं, यह देखने का काम न्यायपालिका का होता है। संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं। उसमें कटौती या कमजोर करने का अधिकार ना तो संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। ना विधायिका को दिया है। नाही कार्यपालिका को दिया है। संविधान ने नागरिकों के समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका को संवैधानिक उपचारों को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। संविधान की मूल भावना है, मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना सरकार कानून और नियम बना सकती है। कार्यपालिका सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी तय की गई है। न्यायपालिका को संविधान मे प्रदत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधायिका और कार्यपालिका काम करे, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई है। 2014 के बाद की न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास लगातार कम हो रहा है। न्यायपालिका आलोचना का शिकार हो रही है। पिछले 10 सालों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन सरकारी कानून से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों से संबंधित कई याचिकाओं पर वर्षों सुनवाई नहीं की है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सरकार को विशिष्ट मानकर फैसला कर रही है। न्यायपालिका यह मानकर चलने लगी है, संसद में जो कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। उसके अनुसार न्यायपालिका को फैसला करना है। गुण दोष के आधार पर अब न्यायपालिका फैसला नहीं कर रही है। राम मंदिर के मामले में आस्था के नाम पर जमीन टाइटल के विवाद पर फैसला दिया गया। उसके बाद से न्यायपालिका द्वारा जिस तरह से फैसले दिए जा रहे हैं। उससे स्पष्ट है, न्यायपालिका यह मानकर चल रही है। सरकार जो भी नियम और कानून बना रही है, वह सही हैं। जिसके कारण संविधान मे प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। नागरिकों को महीनो और वर्षों तक जेलों में असंवैधानिक रूप से बंद रखा जा रहा है। आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लगातार भेदभाव हो रहा है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार गुण दोष के आधार पर फैसला न करके संसद द्वारा बनाए गए कानून और नियमों को सर्वोच्च मानकर फैसला कर रही है। भारतीय न्यायपालिका का 75 वर्षों का इतिहास है। न्यायपालिका ने 65 वर्षों तक गुण और दोष के आधार पर फैसला कर संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन किया। नागरिकों का विश्वास अर्जित किया था। पिछले 10 वर्षों में यह विश्वास कमजोर हुआ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की मंशा के अनुसार मामलों की सुनवाई और निर्णय करने लगे हैं। एक तरह से न्यायपालिका केंद्र सरकार का कवच बन गई है। आम नागरिकों में यह धारणा बनने लगी है। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना नागरिकों का विश्वास न्यायपालिका पर बनाकर रख पाएंगे यह आशा आज के दिन की जा सकती है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप न्यायपालिका के निर्णय होंगे। न्यायपालिका यदि आस्था और सरकार को विशेष मानते हुए कोई फैसला करती है, तो इससे संविधान कमजोर होगा। नागरिकों के अधिकार काम होते चले जाएंगे। 51वें मुख्य न्यायाधीश संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। यही सर्वोच्च प्राथमिक्ता होनी चाहिए।

जम्मू कश्मीर में फिर 370 का राग

सुरेश हिंदुस्तानी

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद नई प्रदेश सरकार ने फिर से पुराने एजेंडे पर काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इससे निश्चित ही यह संकेत मिलता है कि जिस धारा 370 और 35ए के कारण कश्मीर को शेष भारत से अलग दिखने जैसी स्थिति दिखती थी, वैसी ही स्थिति पैदा करने का प्रयास नई सरकार यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा है। राज्य की नई सरकार का यह कदम पाकिस्तान के हौसले बढ़ाने वाला ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान धारा 370 के कारण ही कश्मीर को अपना बताने का कुचक्र रचता रहा है। धारा 370 के बहाने राज्य को मिले विशेष अधिकारों के चलते ही पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क स्थापित किया था, जिसके कारण वहां के नागरिक भारतीय सेना के प्रति अलगाव का व्यवहार करते दिखाई दिए। उस समय पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में युवाओं को भ्रमित करते रहते थे। अब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाव के बीज रोपित करने का काम किया है। जिसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से समर्थन दे रही है। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 कायम थी, तब राज्य ने क्या खोया था, यह पूरा देश जानता है। घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी घटनाएं होती रहती थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को शेष भारत से समरस करने का काम किया है। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा पाने में बहुत हद तक सफल हुआ है।

वर्तमान में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के स्वर मुखरित होने लगे हैं। समान नागरिक कानून निश्चित ही सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का हिमायती है, लेकिन दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अलग संविधान को मान्यता देने वाली धारा 370 को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह धारा जम्मू कश्मीर को अलग पहचान देने का काम करती है। इसके चलते कश्मीर का संविधान और ध्वज अलग हो जाएगा, जो भारत के संविधान और तिरंगा से अलग होगा। यह स्थिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अलग प्रकार की होगी। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वह बयान स्वतः ही खारिज हो जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि भाजपा संविधान फाड़कर फेंकना चाहती है। इसका एक आशय यह भी प्रादुर्भित होता है कि कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कौन से संविधान को बचाना चाहती है, यह और स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी जम्मू कश्मीर को अलग दरजा देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने संविधान में इसको जोड़ने से इंकार कर दिया था। अम्बेडकर जी के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना को दफन करते हुए शेख अब्दुल्ला को प्रसन्न करते हुए धारा 370 का समावेश संविधान में करा दिया। आज कांग्रेस भले ही इस बात का दम्भ भरे कि वह संविधान को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्य ऐसे लगते नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की सरकार ने ही आपातकाल लगाकर भारत के नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए थे, जो बहुत बड़ा संविधान विरोधी कदम था। क्योंकि उस समय आपातकाल लगाने जैसी स्थिति नहीं थी। यह सारा खेल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया गया था। आपातकाल संविधान की हत्या करने जैसा ही था।

पांच वर्ष पूर्व केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाली धारा 370 और 35ए को विलोपित कर दिया। उल्लेखनीय है कि भाजपा का यह कदम किसी भी प्रकार से किसी के विरोध में इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा के हर घोषणा पत्र में इस धारा को हटाने की बात की। इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन मिला। जब जनता ने भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया, तब स्वाभाविक रूप से यही कहा जा सकता है कि भाजपा ने वही काम किया, जो जनता चाहती थी। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान चलता है, राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए उसके संवैधानिक अधिकार सीमित हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार संविधान में बदलाव करने का कोई संवैधानिक हक नहीं रखती। यह केंद्र सरकार का काम है। राज्य कोई विधेयक पारित तो कर सकता है, लेकिन वह विधेयक तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक केंद्र की सरकार न चाहे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य की नवगठित सरकार का यह कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है।

देश में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन बार बार संविधान बचाने की बात करता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने वाले विधेयक पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसे मौन समर्थन भी माना जा सकता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जो धारा 370 और 35ए की बहाली के लिए उनको मजबूर कर रही है। क्या इन दलों को यह पता नहीं है कि इन्हीं कानूनों के कारण ही कश्मीर हिन्दू विहीन हो गया है। क्या यह दल फिर से कश्मीर घाटी को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। देश में एक समान कानून होना चाहिए, यह सभी चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 बहाल हो जाती है तो निश्चित ही पाकिस्तान परस्त मानसिकता फिर से हाबी हो सकती है और जम्मू कश्मीर फिर से अलगाव की स्थिति में आ सकता है। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए कश्मीर में भी देश का संविधान ही लागू रहे, यह समय की मांग है और यह कदम जम्मू कश्मीर के हित का भी है।

राजकुमार रोत को कांग्रेस के लोगों से मैंने छुड़ाया, आदिवासी के घर चाय पी : सीएम

नेता प्रतिपक्ष जूली बाइक पर प्रचार करने निकले

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की सात सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को चौरासी और सलूंबर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा- हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं। हमने वागड़ की धरती को प्राथमिकता में रखा है। मैंने यहां के लिए बजट में कई घोषणाएं की। हमने भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने युवाओं से कहा है आप तैयारी करो। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। इस साल हमने एक लाख नौकरियों का वादा किया है। 33 हजार नियुक्ति पत्र हमने दे दिए हैं।

युवाओं को बरगलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं

मुख्यमंत्री ने सलूंबर में बीएपी का नाम लिए बिना कहा कि ये वो लोग हैं, जिनके बच्चे जयपुर, उदयपुर, कोटा में पढ़ रहे हैं, लेकिन वे आदिवा?सियों को बहका रहे हैं। उनके मन में कोई दर्द नहीं है। वो लोग होशियार हो जाए जो तनख्वाह सरकार की लेते हैं और काम हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम एक-एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार का काम कर रहा है और कौन बरगलाने का काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा- आपके सांसद राजकुमार रोत पहले विधायक थे। उस समय मैं भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री हुआ करता था। तब मैंने टीवी पर देखा कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनके जाकर घेर लिया और उन पर दबाव बना रहे हैं। मैं भाजपा ऑफिस से तुरंत गाड़ी लेकर निकला और उनके घर पहुंचा तो देखा राजकुमार रोत बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मैंने भाजपा के कार्यकर्ता बुलाए और उनको छुड़ाया।

बाइक लेकर गांवों में प्रचार करने निकले नेता प्रतिपक्ष जूली

इधर, कांग्रेस नेताओं ने भी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को रामगढ़ विधानसभा के गांवों में बाइक से प्रचार के लिए निकले। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा सोमवार को जिला कोर्ट पहुंचे। यहां बार एसोसिएशन के ऑफिस गए और वकीलों से समर्थन और वोट देने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग जगह प्रचार करने गए हैं। उधर, दौसा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की।

नवंबर में धूप की तपिश से लोग परेशान, रात की ठंडक दे रही आराम

बाड़मेर। पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में इस समय ठंड का असर देखने को नहीं मिल रहा है। दिन में तेज तपिश और रात में हल्की ठंडक का अनुभव लोग उठा रहे है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री था, जिससे गर्मी का असर बना हुआ है। बाड़मेर में सुबह और देर रात को ठंडक हो रही है, लेकिन सूरज निकलने के बाद तेज धूप से लोग परेशान हो रहे हैं। दिन के तापमान में बढ़ोतरी से कूलर और एसी चल रहे है। रात में भी पंखों चल रहे है। पश्चिम राजस्थान में दिन के तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, पांच की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और दो पुरुष हैं। यह हादसा नोएडा से परी चौक जाते समय हुआ जब एक्सप्रेसवे पर खडे एक खराब ट्रक से एक तेज रफ्तार वैगनार कार से टकरा गई। इस हादसे में कार चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार घायलों ने अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान चारों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्जमाफी

चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर सीएम चुनेंगीं: शाह

महिलाओं को 2100 रुपए महीना

एजेंसी| मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्जमाफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना शिंदे-एनसीपी अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। शाह ने कहा, भाजपा, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन के तीनों सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे।

उद्धव ठाकरे का स्टैंड

उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। आप कहां बैठेंगे इसका फैसला आप ही कीजिए। कहां बैठे हैं, वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वालों की जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं, आप सावरकर का विरोध करने वालों, सीएए-यूसीसी का विरोध करने वालों के साथ हैं।

वक्फ बिल

वे बोले, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए। कर्नाटक के गांव के गांव में मंदिर, खेत, जमीन, घर वक्फ की संपत्ति घोषित किए गए हैं। इसीलिए हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहां भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा।

अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है।

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला हिरासत में

हरदीप सिंह निज्जर का करीबी, पिछले महीने शूटआउट के बाद पुलिस ने पकड़ा था

एजेंसी| ओटावा

खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को कनाडा में हिरासत में लिया गया है। अर्शदीप, हरदीप सिंह निज्जर का करीबी है। दरअसल 28 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन शहर में एक शूटआउट हुआ था। 29 अक्टूबर को वहां की स्थानीय पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया था कि उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की थी। मगर रविवार को सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इनमें से एक आरोपी डल्ला ही है। अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि हिरासत के बाद उसे रिहा किया गया या नहीं। डल्ला की हिरासत पर कनाडा पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

शादी समारोह के कार्ड पर भी चला 'बटोगे तो कटोगे' का नारा

अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा केवल चुनावी राज्यों तक सीमित नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे यह एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। अब तो शादी समारोह का कार्ड भी इस नारे से अछूता नहीं रहा। भावनगर के एक गांव में शादी समारोह चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड में गूंज रहा है।

यूपी के उपचुनाव से पहले बसपा में बड़ी कार्रवाई

तीन पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला, तीन और बड़े नेता भी रडार पर: मायावती

एजेंसी| मेरठ

विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले भी तीनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनके अलावा पश्चिम उप्र के तीन बड़े नेता भी पार्टी हाईकमान के रडार पर हैं। वहीं, प्रशांत गौतम का कहना है कि तीनों को पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है। उप्र की नौ विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है।

राम मंदिर में अब लगेगा मकराना मार्बल, उठ रहे सवाल

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर में कमजोर मार्बल लगाए जाने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर मंदिर निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। भवन-निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि राम मंदिर में लगाए गए मार्बल कई जगहों पर कमजोर दिख रहे हैं। इस कारण इन्हें हटाने और मकराना मार्बल लगाने का निर्णय लिया गया है। मंदिर निर्माण में करोड़ों खर्च होने के बाद यह स्थिति है, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। जानकारी अनुसार राम मंदिर भवन निर्माण समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि कमजोर मार्बल को हटाकर मकराना मार्बल लगाया जाएगा। राम मंदिर के भूतल में गूढ़ी मंडप की दीवारों और स्तम्भों पर सफेद मार्बल लगाया गया है।

इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना लाएंगे: वित्त मंत्री

बेंगलूरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस बार बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी योजना का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं में से चार पहले ही लागू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी योजना का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद इसे तुरंत लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को कर्ज लेने में जोखिम को कम करने के लिए गारंटी दी जाएगी। इसके लिए एक स्ववित्त पोषित गारंटी कोष बनाया जाएगा।

योगी के बयान का विरोध, कहा | ये सब यूपी-झारखंड में चलता होगा

बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा : अजित

एजेंसी| मुंबई

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा-शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजित पवार ने कहा कि, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है- सबका साथ सबका विकास। दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया है। दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं।

शिवसेना बोली- अजित पवार इसका मतलब आगे समझेंगे

अजित पवार के बयान पर शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरूपम ने कहा- योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं। अगर आप एकजुट रहते हैं, तो मजबूत रहते हैं। अजित दादा आज नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा। भाजपा के नारे की न केवल अजित पवार बल्कि विपक्ष की ओर से भी आलोचना की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कल बन जाएंगे देश 51वें प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुर्मू दिलाएंगी शपथ

नई दिल्ली। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वाह्न 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति संजीब खन्ना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए।

महाराष्ट्र के लिए एमवीए का घोषणा पत्र, 5 गारंटी

महिलाओं को 3 हजार रु. महीना, बेरोजगारों को 4 हजार, 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

एजेंसी| मुंबई

महा विकास अघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमपीए ने इसे महाराष्ट्रनामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा- हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3 हजार रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50 हजार रुपए देंगे, जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। मेनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है।

दिल्ली में कनाडाई दूतावास के बाहर प्रदर्शन | बैरिकेडिंग तोड़ी

हिंदू-सिख ग्लोबल फोरम ने ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया

एजेंसी| नई दिल्ली

कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। इस घटना के विरोध में रविवार (10 नवंबर) को दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कार्यकर्ताओं ने कनाडाई दूतावास तक विरोध मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों और फोरम के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारी हिंदू और सिख एकजुट हैं और भारतीय कनाडा में मंदिरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दूतावास के बाहर बैरिकेडिंग की और जवानों को तैनात किया। पुलिस ने दूतावास से पहले तीन मूर्ति मार्ग पर भी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

पीएम मोदी बोले | कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे

जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, सोनिया सरकार चलाती थीं

एजेंसी| रांची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदनकियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा- भाजपा का यहां एक ही मंत्र है हमने झारखंड बनाया है हम ही संवारेंगे। उन्होंने यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीत यूपीए सरकार का भी जिक्र किया। मोदी बोले- जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थीं। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया। राज्य बनने का भी विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा- कांग्रेस और उसके सहयोगी जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाए। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमनें 370 को जमीन में गाड़ दिया है। अब ये इसे कभी नहीं लागू कर पाएंगे। मोदी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना करवाने के वादे पर कहा- कांग्रेस सत्ता के लालच में छोटी-छोटी जातियों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है। इसलिए वे जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं।

कांग्रेस-झामुमो जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है

पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी-छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दें और अपनी-अपनी जातियों में उलझे रहें। क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज टूट जाए? आपको मंजूर है? अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी या नहीं? इसलिए हमें यह याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।

कश्मीर में धारा 370 के लिए साजिश रच रही कांग्रेस

मोदी बोले- जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दीं। कुछ दिन पहले, उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश इसे स्वीकार करेगा? जब भाजपा विधायकों ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया, तो उन्हें विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

कंबोडिया ने मनाई आजादी की 71वीं वर्षगांठ, राजधानी में हुआ भव्य कार्यक्रम

नोम पेन्ह , एजेंसी। कंबोडिया ने शनिवार को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता की 71वीं वर्षगांठ मनाई। यह समारोह देश के राजा नोरोदम सिहामोनी के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री हुन मानेट, सीनेट के अध्यक्ष समदेच तेचो हुन सेन और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष खुओन सुदरी ने भाग लिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राजधानी नोम पेन्ह में स्वतंत्रता स्मारक पर आयोजित एक घंटे के कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान, सिहामोनी ने देश की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता स्मारक के अंदर पुष्पांजलि अर्पित की और औपचारिक विजय अग्नि प्रज्वलित की। शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक संदेश में हुन सेन ने कहा कि 9 नवंबर लोगों को दिवंगत कंबोडियाई राजा फादर नोरोदम सिहानोक द्वारा शुरू किए गए एक महान मिशन की याद दिलाता है। यह मिशन फ्रांसीसी उपनिवेश से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए था। सेन ने कहा, स्वतंत्रता के जनक राजा नोरोदम सिहानोक ने कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने शाही धर्मयुद्ध में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा का बलिदान दिया था। उत्सव के अंत में, स्वतंत्रता और आजादी के प्रतीक के रूप में कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए। फ्रांस ने 1863 में कंबोडिया को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। लगभग 90 वर्षों तक उपनिवेश रहने के बाद, राजा नोरोदम सिहानोक ने 1949 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने की मुहिम शुरू की। 1953 में, वह पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में सफल रहे जब फ्रांस पूरे देश को उपनिवेश मुक्त करने के लिए सहमत हो गया। इस उपलब्धि के कारण कंबोडियाई नागरिकों ने राजा नोरोदम सिहानोक को स्वतंत्रता के पिता के रूप में देखा। आखिरकार कंबोडिया 9 नंवबर 1953 को आजादी हासिल की।

क्वेटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में शनिवार को एक रेलवे स्टेशन पर हुए एक आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। पाकिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता वसीम बेग ने कहा कि विस्फोट में दो लोगों की मौत हो जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, जबकि 62 अन्य घायल हो गए। क्वेटा डिवीजन कमिश्नर हमजा शफकत ने कहा कि यह विस्फोट मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर एक आत्मघाती हमला था, जबकि नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। शफकत ने कहा कि इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि बस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे से स्टेशन बंद करने और ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विस्फोट की कड़ी निंदा की और मृतकों तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान सरकार से घटना की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, निर्दोष लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति यूसुफ रजा गिलानी ने भी घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मानवता के दुश्मन हैं जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।

पुलिस ने कंधार प्रांत में अवैध ड्रग्स के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान, 7 गिरफ्तार

कंधार , एजेंसी। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में काउंटर नारकोटिक्स पुलिस ने पिछले सप्ताह हेरोइन और अफीम सहित अवैध ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मुल्ला असदुल्ला जमशेद ने शनिवार को जानकारी दी कि सात संदिग्ध ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जमशेद ने बताया कि प्रांत के विभिन्न हिस्सों में चलाए गए अभियानों के दौरान अफीम, हशीश और हेरोइन उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस प्रांत में ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता फजल रहीम मुस्किनयार के अनुसार, एक संबंधित मामले में, परवान प्रांत में पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने के संदेह में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पिछले महीने पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान के परवान प्रांत से 33 किलोग्राम अवैध ड्रग्स के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप की टॉप टीम में कौन कौन होगा?

वाशिंगटन, एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने वाले प्रशासन की पहली आधिकारिक नियुक्ति, 2024 के चुनाव अभियान की सह-अध्यक्ष सुसान समरॉल विल्स को अपना चीफ ऑफ स्टाफ घोषित करके किया। 20 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में वापसी से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की चुनाव टीम, पहले से ही कई उम्मीदवारों के प्रोफाइल की जांच कर रही है, जिन्हें व्हाइट हाउस में टॉप पोस्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके साथ काम करने वाले ज्यादातर लोगों को इस कार्यकाल में साथ नहीं रखा जाएगा। हालांकि अमेरिकी मीडिया में कुछ वफादारों की वापसी की अफवाह उड़ाई जा रही है। 78 वर्षीय रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास कई नए सहयोगी हैं, जो उनके मंत्रिमंडल को भर सकते हैं, और उनके प्रशासन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। आइये उन चेहरों के बारे में जानते हैं, जिन्हें ट्रंप मंत्रिमंडल में टॉप पोस्ट मिल सकता है।

चीफ ऑफ स्टाफ - सूसी विल्स : सूसी विल्स और ट्रंप चुनाव अभियान के सह-अध्यक्ष क्रिस लैसिविता, कमला हैरिस पर ट्रंप की जीत के पीछे के प्रमुख चेहरे थे। बुधवार को अपने विजयी भाषण में, उन्होंने उन्हें आइस मेडेन कहा और जीत की क्रेडिट दी, और कहा, कि वह बैकग्राउंड में रहना पसंद करती हैं। अगले दिन विल्स को व्हाइट हाउस में पहली नियुक्ति मिल गई और वो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभावने वाली पहली महिला होंगी। चीफ ऑफ स्टाफ, अक्सर राष्ट्रपति का शीर्ष सहयोगी होता है, जो वेस्ट विंग में दैनिक कामकाज की देखरेख करता है और बॉस के कर्मचारियों का प्रबंधन करता है। 67 वर्षीय विल्स ने दशकों तक रिपब्लिकन राजनीति में काम किया है, रोनाल्ड रीगन के सफल 1980 के राष्ट्रपति अभियान से लेकर व्यवसायी रिक स्कॉट को 2010 में सिर्फ सात महीने में फ्लोरिडा का गवर्नर बनाने तक। रिपब्लिकन ने कहा है, कि वो बड़े लीडर्स को मैनेज करने में माहिर हैं।

ट्रंप का नया अटॉर्नी जनरल : डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर कोई सबसे अहम नियुक्ति होने वाली है, तो वो पद अटॉर्नी जनरल का होगा। क्योंकि, अटॉर्नी जनरल ही जस्टिस डिपार्टमेंट को संभालेगा, जिसने पिछले चार सालों से ट्रंप की नाक में दम कर रखा था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस और विलियम बार, दोनों के साथ असमान संबंधों के बाद, उम्मीद की जा रही है, कि इस बार ट्रंप गलती नहीं करेंगे और सबसे वफादार चेहरे को इस अहम पद पर नियुक्ति देंगे, जो उनके कठोर आलोचकों और विरोधियों को दंडित करने के लिए एजेंसी की अभियोजन शक्ति का उपयोग करेगा। कैबिनेट पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, उनमें टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन शामिल हैं, जिन पर ट्रंप की ही तरह अभियोग लगाया गया और महाभियोग लगाया गया। इसके अलावा, मैथ्यू व्हिटेकर, जिन्होंने ट्रंप के अनुरोध पर सेशंस के पद को छोड़कर तीन महीने के लिए कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल का पद संभाला; माइक डेविस, एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नील गोरसच के लिए क्लर्क थे और जिन्होंने ट्रंप के आलोचकों और पत्रकारों के खिलाफ धमाकेदार धमकियां जारी कीं, और मार्क पाओलेटा, जो ट्रंप के बजट कार्यालय में काम कर चुके हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं।

अमेरिका का नया विदेश मंत्री कौन होगा : अमेरिकी विदेश मंत्री, राष्ट्रपति के विदेश मामलों के मुख्य सलाहकार होते हैं और विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करते समय अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में कार्य करते हैं। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो, जो ट्रंप के उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के रेस में काफी करीब तक पहुंचे थे, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 53 साल के रुबियो, जिन्हें चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, और जिन्होंने 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने मतभेद दूर कर लिए हैं, वो विदेश विभाग संभालने की रेस में सबसे आगे हैं। वे सीनेट की विदेश संबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य और चैंबर के चुनिंदा खुफिया पैनल के उपाध्यक्ष हैं। वहीं, विदेश मंत्रालय पद के लिए अन्य दावेदारों में ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन, टेनेसी के सीनेटर बिल हेगर्टी, जो पहले जापान में ट्रंप के राजदूत थे; और ब्रायन हुक, ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान के लिए विशेष दूत और विदेश विभाग में संक्रमण के प्रयासों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि, नामांकन के लिए एक अज्ञात दावेदार रिचर्ड ग्रेनेल भी हैं, जो ट्रंप के वफादार हैं और जिन्होंने जर्मनी में राजदूत, बाल्कन में विशेष दूत और कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख के रूप में कार्य किया है। 58 वर्षीय ग्रेनेल, ट्रंप की 2020 की चुनावी हार को पलटने के प्रयासों में काफी हद तक शामिल थे।

ट्रंप की जीत के बाद 4बी आंदोलन में शामिल हुईं हजारों अमेरिकी महिलाएं

वाशिंगटन , एजेंसी। 2024 के अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका की लाखों महिलाओं को रास नहीं आई है। हजारों अमेरिकी महिलाएं ट्रंप की जीत के लिए पुरुषों को दोषी ठहरा रही हैं और 4बी आंदोलन में शामिल हो गई हैं, जिसमें उन्होंने बदला लेने और विरोध के तौर पर सेक्स न करने, रिश्ते न बनाने, शादी न करने और बच्चे न पैदा करने की कसम खाई है। 4बी आंदोलन की शुरुआत दक्षिण कोरिया में हुई थी और यह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत को लेकर मचे बवाल के बीच अमेरिका में ट्रेंड कर रहा है। कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक खेमे ने ट्रम्प की नारीवाद विरोधी छवि पेश की। कई अमेरिकी महिलाओं ने वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्हें ट्रम्प की जीत पर आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। अब वो 4बी आंदोलन को अपना रहे हैं। 4बी नाम 4 नंबर से आया है। कोरियाई भाषा में बी नो का संक्षिप्त रूप है। मीटू और एस्केप द कोर्सेट आंदोलनों के बाद यह आंदोलन दक्षिण कोरिया में आया। 4 बीआंदोलन दक्षिण कोरिया में कोई अस्थायी सनक नहीं था और कोरियाई समाज पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 2021 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने कहा कि इस तरह के आंदोलन दक्षिण कोरिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वस्थ संबंधों को अवरुद्ध कर रहे हैं, सीबीसी ने रिपोर्ट की। द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया में जन्म दर में गिरावट देखी गई है और इसमें 4बी आंदोलन की कुछ भूमिका है। अमेरिका में कई महिलाएं सेक्स, शादी, बच्चों और डेटिंग को ना कहती हैं। अब अमेरिका में महिलाएं इसे अपना रही हैं। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी उम्मीदवार मीरा चोई ने एनबीसी को बताया, महिलाओं ने सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे सरकार और राज्य और पुरुष उन्हें विफल कर रहे हैं।

लेबनान में इजरायली हमले जारी, बच्चों सहित 40 लोगों की मौत

बेयरूत, एजेंसी। लेबनान के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पिछले दिनों लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर इजरायली बमबारी के बाद मिली। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार देर रात तटीय शहर टायर में कम से कम सात लोग मारे गए। इजरायली सेना ने पहले शहर के बड़े हिस्से को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन शुक्रवार के हमलों से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सैन्य प्रवक्ता द्वारा कोई आदेश प्रकाशित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और हमले के बाद बरामद किए गए अन्य शवों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को आस-पास के शहरों में हुए हमलों में 13 लोग मारे गए, जिनमें हिज़्बुल्लाह और उसके सहयोगी अमल से जुड़े बचाव समूहों के सात चिकित्सक शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक शहर बालबेक के आसपास पूर्वी मैदानों में शनिवार को इज़राइली हमलों में कम से कम 20 और लोग मारे गए। इजराइली सेना ने कहा कि उसने टायर और बालबेक के क्षेत्रों में हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया।

शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर सकता है बांग्लादेश

ढाका, एजेंसी। अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरूल ने आज कहा है, कि सरकार जुलाई और अगस्त में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं और नरसंहार में कथित रूप से शामिल भगोड़ों को गिरफ्तार करने और देश वापस लाने के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी। सलाहकार आसिफ नजरूल ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मामले की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद कहा, यह कदम जल्द ही उठाया जाएगा। न्यायाधिकरण, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में पुराने उच्च न्यायालय भवन में स्थित है। उन्होंने कहा, हम ईमानदारी से काम करेंगे और उन्हें, जहां कहीं भी वे छिपे हों, वहां से वापस लाने को प्राथमिकता देंगे।

आपको बता दें, कि जुलाई-अगस्त में हुए जन-विद्रोह के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई लोगों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें आईसीटी जांच एजेंसी और अभियोजन टीम के पास अक्टूबर के मध्य तक दर्ज की गई हैं। आपको बता दें, कि भीषण प्रदर्शन के बाद शेख हसीना भागकर भारत आ गईं थीं और उसके बाद से भारत में ही रह रही हैं। मोदी सरकार ने शेख हसीना को फिलहाल शरण दे रखा है और उनका अगला कदम क्या होगा, फिलहाल इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से कई बार मौखिक तौर पर भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की गई है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक, अभी तक आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से शेख हसीना के

प्रत्यर्पण की मांग नहीं की गई है।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि : भारत और बांग्लादेश ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था. ताकि दोनों देशों के बीच भगोड़ों के आदान-प्रदान को आसान और तेज बनाया जा सके। लेकिन, अभी तक प्रत्यर्पण का अनुरोध भारत सरकार को नहीं मिला है। यह संधि कई भारतीय भगोड़ों, खास तौर पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों से जुड़े लोगों के बांग्लादेश में छिपे होने और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने को लेकर अस्तित्व में आई थी। इसका मकसद, बांग्लादेश में छिपे ऐसे लोगों की तत्काल भारत में वापसी सुनिश्चित करनी थी और बांग्लादेश को ऐसे लोग पनाहकार ना बनाएं, उसे भी सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, बांग्लादेश को भी जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) जैसे संगठनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिनके कार्यकर्ता भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में छिपे पाए गए थे। प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है... या जिन पर आरोप लगाया गया है, या जो प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के लिए दोषी पाए गए हैं, या फिर अनुरोध करने वाले देश की अदालत की तरफ से उसे वांटेड घोषित किया गया है।

संधि के मुताबिक, प्रत्यर्पण योग्य अपराध वह है, जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की सजा हो सकती है। इसमें वित्तीय अपराध भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, कि किसी अपराध को प्रत्यर्पण योग्य बनाने के लिए, दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, जिसका अर्थ है, कि वो अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। लेकिन, जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है, कि ये नामुमकिन है, कि भारत सरकार शेख हसीना को किसी भी हाल में बांग्लादेश को सौंपे। लिहाजा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से पंगा लेने के मूड में है और इंटरपोल नोटिस अगर जारी होता है, तो दोनों देशों के बीच का विवाद और बढ़ेगा।

कनाडा में मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, निकला पन्नू का करीबी, संभाल रहा निज्जर का काम

टोरंटो , एजेंसी। कनाडा में मंदिर पर हमला करने के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान ब्राम्पटन के 35 वर्षीय इंदरजीत गोसाल के रूप में हुई है। वह मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी है। ग्रेटर टोरंटो में हिंदू मंदिर पर हमले का प्लान इंदरजीत ने ही तैयार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश देकर छोड़ भी दिया गया। इससे पहले पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इंदरजीत गोसाल सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का दाहिना हाथ है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद वही रेफरेंडम से जुड़े काम को देख रहा है। पुलिस ने बताया, गोसाल को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है और कहा गया कि तय तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना है। बता दें कि 4 नवंबर को खालिस्तानियों ने कनाडा में कई मंदिरों को निशाना बनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन हमलों की निंदा करते हुए कनाडा को कड़ा संदेश दिया था। कनाडा में हिंदुओं पर इस तरह के हमले को लेकर दुनिया

के कई देशों ने निंदा की थी। पुलिस ने कहा, घटना की जांच के लिए एक विशेष दल बनाया गया है और इसकी जांच की जा रही है। हमलों के आरोपियों के पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने देश के कुछ नेताओं पर हिंदुओं और सिखों को जानबूझकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कनाडाई मूल के हिंदू और सिख एक तरफ हैं और खालिस्तानी दूसरी तरफ। आर्य की यह टिप्पणी ब्रैम्पटन के एक मंदिर में हिंदुओं पर हमले की घटना के कुछ दिन बाद आई है। आर्य ने कहा कि कनाडा के कई नेता ब्रैम्पटन की घटना को कनाडाई मूल के हिंदुओं और सिखों के बीच संघर्ष के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के जानबूझकर किए गए कृत्यों और खालिस्तानियों के प्रभाव के कारण कनाडा के लोग अब खालिस्तानियों और सिखों को एक जैसा समझने लगे हैं। खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों की गत तीन नवंबर को ओंटारियो के ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के ब्रैम्पटन शहर में स्थित हिंदू सभा मंदिर में लोगों के साथ झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर अधिकारियों और भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाधा डाली थी। ओंटारियो के नेपियन क्षेत्र से सांसद आर्य ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, कुछ नेता जानबूझकर इस हमले के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार ठहराने और उनका जिक्र करने से बच रहे हैं। वे अन्य तत्वों पर दोष मढ़ रहे हैं। वे इसे हिंदुओं और सिखों के बीच एक मुद्दे के रूप में पेश करके कनाडा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आर्य ने कहा, खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर किए गए हमले को लेकर नेता हिंदुओं और सिखों को इस तरह से चित्रित कर रहे हैं।

कतर ने हमास को देश बाहर निकल जाने का थमाया नोटिस, वाशिंगटन के अनुरोध पर दोहा ने उठाया कदम

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के अनुरोध पर कतर हमास को अपने देश से बाहर निकालने पर सहमति हो गया है। इजरायल-हमास युद्ध को रोकने की कोशिशों के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कतरी समकक्षों को लगभग दो सप्ताह पहले सूचित किया कि उन्हें अपनी राजधानी में हमास को शरण देना बंद करना चाहिए; कतर ने सहमति व्यक्त की और लगभग एक सप्ताह पहले हमास को नोटिस थमा दिया। सीएनएन के अनुसार अमेरिका और कतर के सूत्रों ने बताया कि फिलिस्तीनी ग्रुप को इजरायल-हमास युद्ध में सीजफायर और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए मनाने की कई नाकाम कोशिशों के बाद यह कदम उठाया गया। एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने बताया, हमास एक आतंकवादी समूह है जिसने अमेरिकियों को मारा है और कई को बंधक बनाकर रखा है। बंधकों को रिहा करने के प्रस्तावों को बार-बार खारिज करने के बाद, इसके नेताओं का अब किसी भी अमेरिकी साझेदार की राजधानियों में स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि हमास ने कतर की ओर से फिलिस्तीनी ग्रुप के अधिकारियों को दोहा से निष्कासित करने पर सहमति जताने की खबरों को निराधार और दबाव की रणनीति बताया। हमास ने कहा कि इस तरह के दावे पहले भी मीडिया में बिना किसी सबूत के किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अधिकारी ने शनिवार को कहा, इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि कतर ने अमेरिका के अनुरोध के बाद दोहा से हमास को बाहर निकालने पर सहमति जताई है। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है और यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है। इसे बिना किसी सबूत के दोहराया गया है। अमेरिकी अधिकारी कतर से कहते रहे हैं कि वह हमास के साथ समझौते की चर्चा में निष्कासन की धमकी का लाभ उठाए। हाल ही में अमेरिकी-इजरायली बंधक हर्श गोल्डबर्ग-पोलिन की मौत और हमास द्वारा एक और युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कतर फिलिस्तीनी ग्रुप को बाहर निकालने पर राजी हुआ। पिछले एक साल से इजरायल-हमास युद्ध में सीजफायर करवाने के लिए कतर एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि फिलिस्तीनी ग्रुप के सीनियर मेंबर्स दोहा में रहते हैं। इसी वजह से कतर की राजधानी में प्रमुख वार्ताएं हुई हैं। हमास के कार्यकर्ताओं को कतर से कब निर्वासित किया जाएगा और वे कहां जाएंगे - यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि समूह को देश छोड़ने के लिए अधिक समय नहीं दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी गर्मियों में कतर से कहा कि वह हमास को चेतावनी दे कि अगर ग्रुप गाजा में युद्ध रोकने के लिए सहमत नहीं होता है।

ट्रम्प की एरिजोना समेत सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत: पूरे नतीजे आए, 312 सीटें मिलीं

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के सभी नतीजे सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को अमेरिकी राज्य एरिजोना में भी जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत लिए हैं। एरिजोना की 11 सीटें (इलेक्टोरल वोट) भी उनके खाते में आ गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने 50 राज्यों की 538 में से 312 सीटें जीती हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत पाई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 538 सीटें होती हैं। बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा जरूरी होता है। एरिजोना की गिनती अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में होती है। यहां जीत का अंतर बेहद कम होता है। हालांकि पिछले 70 सालों में डेमोक्रेटिक पार्टी यहां सिर्फ दो बार ही जीत पाई है। 2020 में जो बाइडेन ने एरिजोना में जीत हासिल की थी।

बाइडेन से व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रम्प : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार, 13 नवंबर को अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी शनिवार देर रात दी। अमेरिका में ये परंपरा रही है कि वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव के बाद अगले राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में औपचारिक मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को सत्ता सौंपने की प्रकिया की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रम्प 2020 में जो बाइडेन के हाथों राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने बाइडेन को मुलाकात के लिए आमंत्रित नहीं किया था।

बाइडेन बोले- ट्रम्प को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपेंगे : राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बुधवार को ही राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रम्प को फोन पर जीत के बधाई दी थी। इसके एक दिन बाद यानी गुरुवार को बाइडेन में चुनाव में हुई पर बयान दिया। इस बयान में बाइडेन ने बताया कि उन्होंने ट्रम्प को शांति पूर्वक सत्ता सौंपने का आश्वासन दिया है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि ट्रम्प के सत्ता सौंपने में पूरी तरह मदद की जाए। ये अमेरिकी जनता का हक है। डोनाल्ड ट्रम्प 4 साल बाद दूसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में हराया। डोनाल्ड ट्रम्प ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हार के बाद सत्ता में वापसी की है।

E-Mail: namasterajasthan11@gmail.com, nrnews100@gmail.com

सिर्फ दिवाली पर नहीं, पटाखों पर साल भर हो प्रतिबंध

-शादी व चुनाव में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जताई नाराजगी

नई दिल्ली।पटाखों पर बैन सिर्फ दिखावा है।क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, शादी और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं उन पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए। यह बात दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन लें और पटाखों की ऑनलाइन बिक्री बंद करवायें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध था। क्या पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया।

कोई धर्म प्रदूषण नहीं बढ़ाता, यह लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता।यह लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का मामला है। दिल्ली सरकार पूरे साल पटाखों पर बैन का विचार करे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसके लिए निजी हलफनामा पेश करें।

वक्फ संशोधन के नाम पर मुसलमानों को भूमिहीन बनाने की साजिश : इमरान मसूद

नई दिल्ली। सहारनपुर से सासंद और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि वक्फ संशोधन के नाम पर मुसलमानों को भूमिहीन बनाने की साजिश की जा रही है। वह रविवार रात यहां मोती डूंगरी रोड पर हुई 'तहफ्फुजे औकाफ कॉन्फ्रेंस' में बोल रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने के मकसद से 'विमर्श' गढ़ने की कोशिश कर रही है। मसूद ने कहा कि मुसलमानों के सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण करने संबंधी दावे ''भ्रामक'' हैं और ये प्रस्तावित संशोधन को सही ठहराने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मुसलमानों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को ही सरकार की जांच का सामना करना पड़ रहा है। मसूद ने कहा कि यह ''मुसलमानों को भूमिहीन करने की योजना'' का हिस्सा है। आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने कहा कि जेपीसी को विधेयक पर वास्तविक हितधारकों के विचारों को समझने के लिए उनसे मशविरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''इसके बजाय, वह ऐसे व्यक्तियों और समूहों को समय दे रही है जो न तो हितधारक हैं और न ही उन्हें वक्फ की कोई समझ है।'' खान ने कहा, ''यह निराशाजनक है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुति देने की अनुमति दे रहे हैं जिनका ध्यान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करने या इससे इतर मामलों पर चर्चा करने पर रहता है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथी मृत पाया गया

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सोमवार को धान के खेत में एक हाथी मृत पाया गया। वन अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक वन अधिकारी ने बताया कि नर हाथी का शव आज सुबह वाड्राफनगर वन रेंज के अंतर्गत मुरका गांव में बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि हाथी छह हाथियों के झुंड का हिस्सा था जो पिछले कुछ दिनों से इलाके में घूम रहा था। अधिकारी ने बताया कि सुबह इसकी सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि मौत के पीछे का सही कारण जानने के लिए जांच चल रही है। जांच के बाद ही जानकारी मिल सकेगी कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई या इसका कोई अन्य कारण हो सकता है। राज्य के रायगढ़ जिले के एक वन क्षेत्र में 26 अक्टूबर को एक शावक सहित तीन हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई थी। एक नवंबर को बिलासपुर जिले में एक हाथी के शावक की करंट लगने से मौत हो गई थी। अधिकारियों ने पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ में पिछले छह सालों में करीब 80 हाथियों की मौत हुई है, जिसकी वजह बीमारी और उम्र से लेकर बिजली का करंट तक है। राज्य के उत्तरी हिस्से में मानव-हाथी संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का प्रमुख कारण रहा है। मुख्य रूप से सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले इस खतरे का सामना कर रहे हैं।

ओडिशा के बालासोर में बंद पड़ी पत्थर खदान से मानव कंकाल मिला

ओडिशा के बालासोर जिले के तियाकाटा गांव में पुलिस ने एक बंद पड़ी पत्थर खदान से एक मानव कंकाल बरामद किया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को नीलगिरी उपखंड के बेरहामपुर इलाके में एक सुदूर पहाड़ी इलाके में लंबे समय से बंद पड़ी एक पत्थर खदान से कंकाल बरामद किया गया। पुलिस को कंकाल के बारे में तब पता चला जब कुछ स्थानीय लोगों ने बकरी चराने के लिए जंगल में जाते समय इसे देखा। नीलगिरि के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सरोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच के लिए सोमवार सुबह पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि कंकाल के नमूने जांच के लिए फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी (एफएमटी) भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया, ''हम जंगल में इस सुनसान और दुर्गम स्थान से बरामद कंकाल के विवरण के बारे में फिलहाल कुछ नहीं जानते हैं।'' पुलिस ने बताया कि यह हत्या, आत्महत्या या फिर जंगल में टहलते समय लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति के खाई में गिरने का मामला हो सकता है।

हमारे पास केंद्र सरकार से ज्यादा धन, मेरे सामने उनकी क्या औकात?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा-9 हजार बीघा ज़मीन गरीबों को बांटी

रांची (एजेंसी)। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के चक्रधरपुर में एक चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनके पास केंद्र सरकार से ज्यादा धन है और उन्होंने 9 हजार बीघा ज़मीन गरीबों को बांटी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी में पीएम मोदी के निजी सहायक को दवा नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने पीएम के पीए को दवा पहुंचाई थी। मेरे सामने मोदी की क्या औकात है? यादव ने आगे दावा किया कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सात करोड़ रुपए की रेमडेसिविर दवा खरीदकर लोगों में बांटी थी और हर गरीब के घर-घर पैसा पहुंचाया था। पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में झारखंड में चुनावी रैलियां कर रहे हैं।

पप्पू यादव ने दावा किया कि वह अकेले पूरे देश का इलाज करवा सकते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पूरे कोरोना काल में हर गरीब को दो-दो हजार रुपए दिए। क्या किसी और की इतनी औकात है? उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए टारगेट कभी मोदी या अन्य नेता नहीं होते, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य देश के गरीबों की मदद करना होता है।

इसके अलावा यादव ने शारदा चिटफंड घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का नाम शारदा घोटाले में आया था और सीबीआई ने उनके यहां छापेमारी की थी। उन्होंने कहा कि 2014 में सीबीआई ने हिमंत बिस्वा सरमा से 4 घंटे तक पूछताछ की थी। आज वह किस पार्टी में हैं? पप्पू यादव के इस आरोप से उनकी आलोचना करने वालों को भी मौका मिला है, लेकिन यादव ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे।

पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के कामकाजी सिद्धांतों और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और अपने समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। यादव का यह बयान आगामी चुनावों में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि उनके बयानों ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया है।

झारखंड में भाजपा की जड़ें उखाड़ देगा 'इंडिया' गठबंधन : लालू

रांची । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद ने दावा किया कि झारखंड में सत्तारूढ़ 'इंडिया' गठबंधन राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जड़ें उखाड़ देगा। लालू ने कहा कि 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन भाजपा की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा है। 'इंडिया' गठबंधन में राजद भी शामिल है। झारखंड के कोडरमा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू ने कहा, 'हम भाजपा की जड़ें उखाड़ देंगे और वह कभी वापसी नहीं कर सकेगी। भाजपा हमारी ताकत के आगे बेबस है।' बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो देश में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, 'मैंने कोडरमा के विकास में योगदान दिया है। इसलिए, हमारे उम्मीदवार सुभाष यादव को वोट देना न भूलें और उनकी जीत सुनिश्चित करें।' कोडरमा विधानसभा क्षेत्र दस साल पहले तक राजद का मजबूत गढ़ हुआ करता था। हालांकि, 2014 में भाजपा की नीरा यादव ने राजद से यह सीट छीन ली। नीरा कोडरमा से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने की उम्मीद के साथ एक बार फिर मैदान में हैं। राजद के सुभाष यादव इस बार 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कोडरमा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें राजद सुप्रीमो का करीबी सहयोगी माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में सुभाष यादव को हाल ही में जमानत दी थी।

मैं व्यवस्था को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं

-पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद कई मुद्दों पर रखे विचार

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ रविवार को अपने पद से रिटायर हो गए। उनकी जगह आज यानी सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ ली। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण, आरक्षण, कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों और जजों के वेतन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने एक बात और कही कि मुझे लगता है कि मैंने व्यवस्था को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं, जहां वह पहले था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आठ साल से ज्यादा समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज और पिछले दो साल तक चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें लगता है कि उन्होंने व्यवस्था को उससे बेहतर बनाया है जितना उन्हें मिला था। उन्होंने दिव्यांग अधिकारों, सूचना के अधिकार, आर्थिक संघवाद और लिंग और जातिगत भेदभाव के संदर्भ में समान अवसर के सिद्धांत पर दिए गए अपने फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ नफरत फैलाने वाले भाषणों का असर कई गुना बढ़ गया है और ये लोगों के मन और भावनाओं पर गहरा असर डाल रहे हैं।

इस सवाल का जवाब में चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र के कोई समान घटक नहीं हैं जिन्हें हर देश को यह तय करने के लिए पूरा करना चाहिए कि वह लोकतांत्रिक रूप से काम कर रहा है। भारत में लोकतांत्रिक कामकाज का आधार, जहां हम अपनी अनूठी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अन्य देशों में लोकतंत्र के आधार से अलग है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हम लोकतंत्र की केवल राजनीतिक समझ को नहीं मानते हैं। चुनाव या प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे जैसे मतदान का अधिकार या सीमा निर्धारण, लोकतांत्रिक शासन का हिस्सा हैं।

अखिलेश यादव का हमला, युवाओं से धोखा करने वाली बीजेपी को हराना अब वक्त की जरूरत है

लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और कार्यकर्ताओं से आगामी उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां न केवल जनता के लिए नुकसानदायक रही हैं, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है।

अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अखिलेश ने कहा, 'बीजेपी सरकार युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और इस कारण वे लगातार नाराज हैं।' उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से युवाओं के हक के लिए लड़ती आई है, और आगामी उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर काम करना होगा।

सपा अध्यक्ष ने बीजेपी की नकारात्मक राजनीति पर भी कड़ा विरोध जताया और कहा कि पार्टी देश की जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जिस दिशा में बढ़ रही है, वह वही से जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। उनका दावा था कि बीजेपी को गठबंधन ने पहले भी हराया था और अब पार्टी प्रदेश में पीडीए (प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन) से डरने लगी है।

सम्भल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भी इस जनसभा में बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुंदरकी उपचुनाव के लिए पुलिस को हटाकर एक निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहिए। बर्क ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर बना हुआ है, और आगामी उपचुनाव में सपा की जीत सुनिश्चित है।

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गुस्सा किसी और वजह से है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि दिल्ली में यह फैसला हो चुका है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में आ सकती है। अखिलेश ने बीजेपी की कुटिलता और विनाशकारी मानसिकता की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार केवल विभाजन की राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रदेश की असल समस्याओं की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में घोटाले और प्रश्नपत्र लीक होने जैसी घटनाएं युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन चुकी हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण के मामले में बीजेपी सरकार द्वारा दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि वे आगामी चुनाव में पुलिस-प्रशासन द्वारा वोटिंग में हेरफेर की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त न करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी ने वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी की या वोट काटने की कोशिश की, तो सपा उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे वोटर लिस्ट की निगरानी करें और अगर किसी का नाम हटाया जाता है तो उसकी फोटो कॉपी तैयार रखें ताकि उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके।

अखिलेश ने जनता से भी अपील की कि वे हर घटना का वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करें ताकि भविष्य में सबूत के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती और केवल बाहरी दिखावे का ढोंग रच रही है। अखिलेश ने विश्वास दिलाया कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी और आने वाला समय समाजवादियों का होगा अखिलेश यादव ने जनता से एकजुट होकर आगामी उपचुनाव में बीजेपी को हराने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि सपा के नेतृत्व में प्रदेश में बदलाव आएगा।

एक हजार किमी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगी नेवी

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक हजार किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के टारगेट पर हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नेवी परीक्षण करने जा रही है। ये वो मिसाइल है जो सरफेस शिप्स और तटीय ठिकानों दोनों से ही टारगेट को भेदने की ताकत रखती है। भारतीय रक्षा बलों की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मिसाइल का टेस्ट अगले कुछ दिनों में होने वाला है। इसे देश के पूर्वी तट पर किया जाएगा। इस मिसाइल प्रणाली के जरिये नौसेना को बैलिस्टिक मिसाइलों का मजबूत भंडार बनाने में मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल संघर्षरत देशों में किया जा रहा है। ये मिसाइल्स नौसेना को सरफेस शिप्स और तटीय ठिकानों दोनों से ही टारगेट को भेदने में सक्षम बनाएंगी।

बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने भी हाल ही में युद्धपोत से 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तानी नौसेना ने बताया था कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम जमीन और समुद्र के टारगेट्स को अत्यंत सटीकता से भेदने में सक्षम है। हालांकि, भारत जिस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, उसकी रेंज पाकिस्तान के इस मिसाइल सिस्टम से काफी ज्यादा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा बलों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना रहा है। बता दें कि रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला भारत की मध्यम दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के पास ये पहले से ही मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक प्रलय मिसाइलों का वर्तमान में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। इनके जल्द ही ऑपरेशनल सर्विस के लिए तैयार होने की उम्मीद है।सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलने और कई नई तकनीकों वाली इन मिसाइलों की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। रॉकेट फोर्स परियोजना सामरिक रॉकेट फोर्स विकसित करने के सशस्त्र बलों के प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। बता दें कि सेनाएं सीमा पर खतरों का मुकाबला करने के लिए रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रही हैं।

बारिश-भूस्खलन का असर, चार धाम में 10 लाख श्रद्धालु घटे

-अब तक 46.74 लाख यात्रियों ने किए दर्शन

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के चलते इस साल चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। अब तक 46.74 लाख यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए हैं। बता दें कि ठंड बढ़ने के साथ उत्तराखंड के चारधामों में कपाट बंद हो जाते हैं।? केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पूरी हो चुकी है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ यात्रा का समय पूरा हो जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर बारिश 20 दिन ज्यादा रही। इस कारण सामान्य से 12 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई। सामान्य तौर पर यहां 1121 एमएम बारिश होती है पर इस बार 1230 एमएम बारिश हुई। केदारनाथ की सड़क एक महीना बंद रही मई से लेकर जुलाई मध्य तक करीब 31 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके थे। इसके बाद मॉनसून की जोरदार बारिश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूट पड़ा। 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग में बादल फटने के बाद सोन प्रयाग के पास करीब 150 मीटर हाईवे बंद हो गया। हाइवे दोबारा तैयार होने में एक महीने से अधिक समय लगा।

2023 में रिकार्ड लोगों ने की थी यात्रा

2023 में यात्रियों की संख्या 56 लाख से अधिक थी। ये यात्रा के इतिहास में सबसे अधिक यात्रियों की संख्या होने का रिकॉर्ड है। चार धामों में सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस साल 16.52 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं,12.98 लाख बद्रीनाथ, 8.15 लाख गंगोत्री और 7.14 लाख श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। 1.83 लाख श्रद्धालु श्री हेमकुंटसाहिब भी दर्शन को पहुंचे। पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदिकैलाश के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हो चुके हैं। इस साल आदिकैलाश में 40 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। जो यहां पहुंचने वाले यात्रियों की आज तक की सबसे बड़ी संख्या है।

अमेरिका में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी

-2023 में 41,330 शरण आवेदन आए जिसमें सबसे ज्यादा गुजराती थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या में पिछले तीन सालों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 4,330 शरण आवेदक थे, जबकि 2023 में यह संख्या 855 फीसदी से बढ़कर 41,330 पर पहुंच गई है।

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इन आवेदकों में से आधे से ज्यादा गुजरात के रहने वाले हैं। 2023 में भारतीयों द्वारा की गई शरण आवेदन संख्या अमेरिका में रक्षात्मक शरण मांगने वालों में पांचवीं सबसे बड़ी थी, जबकि पॉजिटिव शरण आवेदनों में यह सातवीं सबसे बड़ी संख्या थी। 2023 शरणार्थी एनुअल फ्लो रिपोर्ट में बताया गया था कि 2023 में 5,340 भारतीयों को अमेरिका में शरण मिली थी।

वित्त वर्ष 2021 में शरण आवेदनों की संख्या 4,330 थी, जिसमें अफर्मेटिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार के आवेदन थे। 2022 में यह संख्या करीब तीन गुना बढ़कर 14,570 हो गई। 2023 में यह बढ़ोतरी जारी रही और भारतीय शरण आवेदनों की संख्या 41,330 हो गई, जो पिछले साल से करीब तीन गुना ज्यादा थी। अफर्मेटिव आवेदन वे होते हैं जब कोई व्यक्ति निष्कासन प्रक्रिया में नहीं है और वह सीधे अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के जरिए से शरण के लिए आवेदन करता है। अगर इमिग्रेशन सर्विसेज आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो व्यक्ति को निष्कासन कार्यवाही में भेजा जाता है। डिफेंसिव आवेदन वे होते हैं जब कोई व्यक्ति निष्कासन प्रक्रिया में शामिल होता है और शरण के लिए न्यायालय में आवेदन करता है, ताकि उसे निष्कासन से बचाया जा सके। 2023 में 5,340 भारतीयों को शरण मिली, जिसमें से 2,710 अफर्मेटिव आवेदन और 2,630 डिफेंसिव आवेदन थे। इस प्रकार भारत अफर्मेटिव शरण अनुदान के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में पांचवे स्थान पर पहुंच गया है।

हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र

NAMASTE RAJASTHAN

नमस्ते राजस्थान

खबरों की सत्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता

E-MAIL
namasterajasthan11@gmail.Com
nrnews100@gmail.com

राजस्थान
08
भीलवाड़ा

मंगलवार,12,नवम्बर, 2024

खबर संक्षेप

नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने शीर्ष नेतृत्व को बदला

नई दिल्ली। टीवीएस मोटर की इकाई ब्रिटिश बाइक विनिर्माता नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने अपने शीर्ष नेतृत्व में सोमवार को बदलाव किया। इसके साथ ही अब कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रॉबर्ट हेंटशेल तत्काल अपने पद से हट जाएंगे और गैर-कार्यकारी निदेशक की भूमिका में आ जाएंगे।

ओडिशा के स्टार्टअप ने शुरू की ड्रोन लॉजिस्टिक सेवा

भुवनेश्वर। ओडिशा स्थित स्टार्टअप बॉनवी एयरो ने पूरी तरह से स्वायत्त लॉजिस्टिक ड्रोन सेवा एयर ओर्का की शुरुआत की है। इस ड्रोन सेवा का शुभारंभ उद्यम पूंजीपति टिम ड्रेपर की मौजूदगी में किया गया। सत्यव्रत सतपथी ने कहा, इस ड्रोन सेवा का उद्घाटन भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र और ओडिशा स्थित कंपनी के रूप में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

गॉडफ्रे फिलिप्स का शुद्ध लाभ 23 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। सिगरेट बनाने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 23 प्रतिशत बढ़कर 248.31 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 202.06 करोड़ रुपये रहा था। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (जीपीआईएल) ने सोमवार को

वेदांता की अवानस्ट्रेट इंक में निवेश करने की योजना

नई दिल्ली। धातु और खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड अपनी डिस्प्ले ग्लास इकाई अवानस्ट्रेट इंक में करीब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। वेदांता समूह ने भारत में डिस्प्ले सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई है। एक बयान में कहा गया, ''वेदांता

अरुण दुग्गल ने इक्रा बोर्ड का चेयरमैन पद छोड़ा

नई दिल्ली। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को कहा कि उसके बोर्ड के चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अरुण दुग्गल ने कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। इक्रा ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरुण दुग्गल और रंजना अग्रवाल की नियुक्ति का लगातार दूसरा कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 को समाप्त हो गया। ऐसे में दुग्गल इक्रा लिमिटेड के चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक नहीं रहेंगे।

ओरिएंट ग्रीन पावर का मुनाफा घटकर 66.46 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली। ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत घटकर 66.46 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 75 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। ओरिएंट ग्रीन पावर ने सोमवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 126.13 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 124.10 करोड़ रुपये थी।

मारुति की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली यह कार

मारुति डिजायर का नया संस्करण पेश, कीमत 6.79 लाख से शुरू

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

देश की प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार डिजायर का नया संस्करण पेश किया। कंपनी ने कहा है कि घरेलू बाजार में अपनी उच्च हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए कंपनी प्रत्येक ग्राहक वर्ग की जरूरतों को पूरा करना जारी रखेगा। मारुति सुजुकी की नई डिजायर को एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस जैसे 4 ट्रिम में कुल 9 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनमें दो सीएनजी वेरिएंट भी हैं। इनकी एक्स शोरूम प्राइस 6.79 लाख रुपये से शुरू होकर 10.14 लाख रुपए तक है।

ये इंट्रोडक्ट्री प्राइस हैं। आप इसे 18,248 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन फीस पर रेंट भी कर सकते हैं। बाकी इस कॉम्पैक्ट सेडान को सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, वाइट, रेड और ब्राउन जैसे 7 आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इस कार की बुकिंग जारी है और डिलीवरी शुरू होने वाली है।

नई मारुति सुजुकी डिजायर बिल्कुल ही नए अवतार में आई है। हालांकि, इसके डायमेंशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फ्रंट फेसिया बिल्कुल नई है। इस सेडान में स्ट्राइकिंग वाइड फ्रंट फेसिया के साथ ही एलईडी क्रिस्टल विजन हेडलैंप्स, 3डी ट्रिनिटी रियर लैप्स, एयरो बूट लिप स्पॉयलर, डुअल टोन अलॉय व्हील समेत और भी का काफी सारी बाहरी खूबियां दिखती हैं। मारुति ने अपनी नई डिजायर सेडान को स्टाइलिश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

पुराने मॉडल के मुकाबले काफी सारे नए फीचर्स व लुक

अपग्रेडेड इंटीरियर और लेटेस्ट फीचर्स

ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंपल और क्लीन डुअल टोन इंटीरियर, स्पेसियस केबिन, वाइड स्वीपिंग सेंट्रल गार्निश के साथ ही सेगमेंट में सबसे बड़ा 9 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक एसी, सुजुकी कनेक्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स और 15 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं।

5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली पहली मारुति कार

ऑल न्यू डिजायर को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है और इसने क्रैश टेस्ट की एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटिगरी में अच्छे-खासे पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसमें इलेक्ट्रोनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर समेत अन्य खूबियां हैं।

दोनों ही कंपनियां सीसीआई की जांच का सामना कर रहे

जोमैटो, स्विगी ने कहा कि वे प्रतिस्पर्धा कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए सीसीआई की जांच का सामना कर रहे ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति मंच जोमैटो ने दावा किया है कि वह देश के कानूनों का अनुपालन करती है, जबकि स्विगी का कहना है कि वह स्थानीय नियमों का अनुपालन करने को प्रतिबद्ध है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर दोनों कंपनियों ने मीडिया की उन खबरों को ''भ्रामक'' करार दिया जिसमें जोमैटो और स्विगी द्वारा कुछ रेस्तरां भागीदारों को कथित तरजीह देने की बात कही गई है। दोनों मंचों ने कहा कि सीसीआई ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के मामले पर अभी तक अपना अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, सीसीआई ने चार अप्रैल 2022 को एक '' प्रथम दृष्टया '' आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग के महानिदेशक के कार्यालय को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत संभावित उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

जोमैटो का दावा वह कानून का अनुपालन करती है

रिपोर्ट नियामक को सौंप दी गई

हालांकि, सूत्रों के अनुसार, सीसीआई की जांच में पाया गया कि दोनों खाद्य आपूर्ति मंच अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त हैं जिसमें कुछ भागीदार रेस्तरों को कथित रूप से तरजीह देना भी शामिल है। सीसीआई ने अप्रैल 2022 में विस्तृत जांच का आदेश दिया था और जांच रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में नियामक को सौंप दी गई थी।

आयोग के साथ मिलकर काम जारी रहेगा

कंपनी ने कहा, पांच अप्रैल 2022 की सूचना के बाद से आयोग ने गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। जोमैटो ने सूचना में कहा, '' तदनुसार, उपर्युक्त खबर भ्रामक है। हम आयोग के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि हमारी सभी प्रथाएं प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुरूप हैं और उनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।''

संचालन के कुछ पहलुओं की ही जांच

दूसरी ओर स्विगी ने बयान में कहा, उसके खिलाफ सीसीआई की जांच से जुड़ी मीडिया की खबर जांच प्रक्रिया और अंतिम परिणाम को भ्रमित करती हैं। बयान के अनुसार, '' सीसीआई के पांच अप्रैल 2022 के आदेश के आधार पर महानिदेशक ने हमारे व्यवसाय के संचालन के कुछ पहलुओं की जांच की। इसकी जांच तथा मार्च 2024 की रिपोर्ट सीसीआई द्वारा जारी जांच में एक प्रारंभिक कदम है, न कि अंतिम निर्णय जैसा कि कुछ खबरों में दावा किया गया है।''

कंपनी ने कहा कोई गोपनीय विवरण नहीं मिला

कंपनी ने कहा कि महानिदेशक के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए उसे अभी तक सीसीआई से निष्कर्षों का गोपनीय विवरण नहीं मिला है। उसने कहा, '' एक बार जब स्विगी अपना जवाब दे देगी और सीसीआई इस मामले पर सुनवाई करेगी... फिर सीसीआई इस पर अपना निर्णय पारित करेगी कि क्या कोई प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं।

प्रथाओं के संबंध में कोई अंतिम निर्णय जारी नहीं

वर्तमान में यह प्रारंभिक चरण में है और 2022 से स्विगी की प्रथाओं के संबंध में कोई अंतिम निर्णय या आदेश जारी नहीं किया गया है।'' स्विगी ने कहा कि वह '' जांच में पूर्ण सहयोग कर रही है और देश के मौजूदा कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

सेंसेक्स व निफ्टी स्थिर रुख के साथ हुए बंद

मुंबई। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सपाट बंद हुए। इस दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली जारी रहने, कंपनियों के निराशाजनक तिमाही नतीजों और कमजोर एशियाई बाजारों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

सेंसेक्स 9.83 अंक या 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,496.15 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 80,102.14 अंक के ऊपरी और 79,001.34 अंक के निचले स्तर को छुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 6.90 अंक या 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,141.30 अंक पर बंद हुआ।

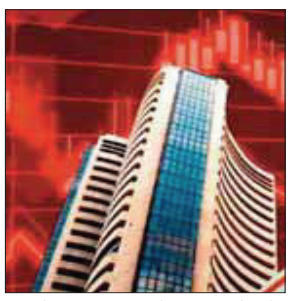

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 3,404.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा कि भारतीय बाजार दबाव में हैं, जिसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है।

इन शेयरों को हुआ नुकसान

सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक आठ प्रतिशत की गिरावट एशियन पेंट्स में हुई। इसके अलावा टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी नुकसान में बंद हुए।

पावर ग्रिड में रही तेजी

दूसरी ओर पावर ग्रिड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 41,887 करोड़ रुपए का निवेश

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्टूबर में 41,887 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश आया है। यह मासिक आधार पर 21.7 प्रतिशत की वृद्धि है। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद इसे विशेष क्षेत्रों के आधार पर निवेश करने वाले कोषों में मजबूत निवेश से बल मिला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह शेयरों में निवेश करने

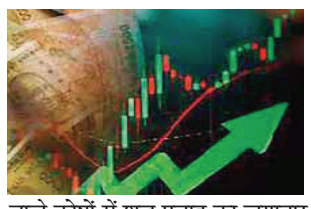

वाले कोषों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 44वां महीना है, जो निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। इसके अलावा, व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) से मासिक योगदान अक्टूबर में बढ़कर 25,323 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर में यह 24,509 करोड़ रुपये था। एम्फी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकट चलसानी ने कहा कि उद्योग की मजबूत वृद्धि का पता इस बात से चलता है कि खुदरा फोलियो की संख्या 17.23 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें एसआईपी खातों में निरंतर वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। एसआईपी खातों की संख्या अब 10.12 करोड़ से अधिक हो गई है।

हाल के वर्षों में शेयर बाजार में तेज गिरावट रही

जोसफ ने कहा, ''सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में पांच-छह प्रतिशत की गिरावट हाल के वर्षों में सबसे तेज गिरावट में से एक है, जो कि हमने आखिरी बार मार्च, 2020 में देखी थी। इसके बावजूद, खुदरा निवेशकों ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है।''

'यूके' कोड बन जाएगा इतिहास एयर इंडिया-विस्तारा का विलय

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली/मुंबई

करीब 10 साल पुरानी एयरलाइन विस्तारा ने आसमान को अलविदा कह दिया। इस प्रतिष्ठित पूर्ण सेवा एयरलाइन ने सोमवार देर रात एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अपनी आखिरी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया। विस्तारा की उड़ान 'यूके 986' मुंबई से दिल्ली और 'यूके 115' दिल्ली से सिंगापुर के लिए रही।

यह आखिरी बार था जब उड़ान कोड 'यूके' आसमान में दिखाई दिया और मंगलवार से विस्तारा की उड़ानों का नया कोड 'एआई2एक्सएक्सएक्स' होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब एयरलाइन ने नौ जनवरी, 2015 को परिचालन शुरू किया था, तो पहली उड़ान दिल्ली से मुंबई के लिए संचालित हुई थी।

सोमवार को एक अधिकारी ने बताया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर विस्तारा की आखिरी उड़ानें क्रमशः 'यूके 986' और 'यूके 115' होगी। 'यूके 986' को मुंबई से दिल्ली के लिए लगभग 10.50 बजे रवाना होना है और 'यूके 115' को दिल्ली से सिंगापुर के लिए रात लगभग 11.45 बजे रवाना होना है। विस्तारा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "इस अविस्मरणीय यात्रा का हिस्सा बनने और हमें प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। हम इन यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे। अब सभी नवीनतम जानकारी के लिए एयर इंडिया को 'फॉलो' करें।" टाटा समूह और सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय किया जाएगा, जिसके बाद विस्तारित इकाई में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1 प्रतिशत होगी। यह विलय देश के तेजी से बढ़ते नागर विमानन क्षेत्र में 2006-2007 के बाद दूसरे बड़े एकीकरण का दौर होगा।

वित्त वर्ष 2006-07 में इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में और एयर सहारा का जेट एयरवेज में विलय हुआ था। इसी दौरान एयर डेक्कन का किंगफिशर एयरलाइंस में विलय हुआ। विस्तारा के विलय के बाद पूर्ण सेवा भारतीय एयरलाइन के रूप में केवल एयर इंडिया ही रह जाएगी।

दीपावली पर मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री हुई दोगुनी

इंदौर (मध्यप्रदेश)। देश में इस बार दीपावली के त्योहारी मौसम के दौरान मिठाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। उद्योग जगत के एक महासंघ का अनुमान है कि दीपावली पर मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री दोगुनी बढ़कर करीब 5,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई।

फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक फिरोज एच. नकवी ने सोमवार को बताया, /"दीपावली के मौके पर लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों, परिचितों और सहकर्मियों के लिए तोहफे के रूप में मिठाइयों के ऑनलाइन ऑर्डर में खासी तेजी देखी गई। हमारा अनुमान है कि दीपावली पर देश में मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री 5,000 करोड़ रुपये के आस-पास रही।

नकवी ने बताया कि देश में पिछले साल मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री लगभग 2,300 करोड़ रुपये के स्तर पर रही थी। नकवी ने बताया, ग्राहकों के मौजूदा रुझान को देखते हुए हमें लगता है कि अगले पांच साल तक मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री में तेजी बनी रहेगी।

काजू की मिठाईयों की मांग ज्यादा रही

नकवी ने बताया, इस बार दीपावली पर काजू कतली और काजू से बनी दूसरी मिठाइयों, सोन पापड़ी और बेसन की अलग-अलग मिठाइयों की सबसे ज्यादा मांग रही।/" उन्होंने बताया कि देश में पिछले साल दीपावली पर लगभग 19,000 करोड़ रुपये की मिठाइयां बिकी थीं जिसमें ऑनलाइन बिकी मिठाइयां शामिल हैं।

सोना 450 रुपए और चांदी 600 रुपए टूटी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 450 रुपये की गिरावट के साथ 79,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को सोना 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 600 रुपये टूटकर 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 94,600 रुपये प्रति किलोग्राम था। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 450 रुपये घटकर 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। शुक्रवार को यह 79,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

भारत के लिए खड़ी होंगी कई नई चुनौतियां, ट्रंप की जीत से डॉलर हुआ काफी मजबूत

अब तक के रिकॉर्ड तोड़ रसातल में पहुंचा भारतीय रुपया

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार गिरावट जारी है। लगातार चौथे दिन रुपया गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 84.39 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भारतीय बाजार में बिकवाली और फंड आउटफ्लो की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है।

इसके अलावा, आगामी अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से डॉलर की मजबूती बढ़ने की आशंका है, जिससे रुपए में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुद्रा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में टैक्स में कटौती और नियमों में ढील से आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

रुपए की कमजोरी भारत के लिए कई नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। डॉलर के मजबूत होने का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अक्टूबर में 1 डॉलर के लिए 83 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब 84.39 रुपए खर्च करने होंगे। भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है, जो डॉलर की मजबूती से और महंगा हो जाएगा, जिससे आयात खर्च बढ़ेगा और घरेलू बाजार में कई वस्तुओं के दामों पर दबाव बनेगा।

एफपीआई डॉलर को देंगे प्राथमिकता

इसका असर डॉलर की मजबूती पर पड़ेगा, जिससे विदेशी निवेशक डॉलर में निवेश को प्राथमिकता देंगे। साथ ही, अमेरिकी टैरिफ में संभावित वृद्धि से यूरो और अन्य एशियाई मुद्राओं पर भी दबाव रहेगा, जिससे रुपए पर संकट गहराने की संभावना है।

क्रूड ऑयल का आयात होगा महंगा

रुपए में गिरावट भारत के लिए परेशानियों के नए दरवाजे खोल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल के आयात पर पड़ेगा। भारत बड़े स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का आयात करता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान किया जाता है। रुपए में गिरावट से भारत का आयात खर्च बढ़ेगा, जिसका असर पेट्रोल-डीजल के दामों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में कच्चे माल के तौर पर उपयोग होते हैं। इसके साथ ही, रुपए की

स्वात्वाधिकारीः प्रकाशक एवं मुद्रकः पंकज गर्ग द्वारा नमस्ते राजस्थान 14/71, प्रेम भवन, चितौडवालो की हवेली के पास, इंद्रा मार्केट के सामने, शाम की सब्जी मंडी रोड, भोपालगंज, भीलवाड़ा, राजस्थान 311001 से प्रकाशित एवं डीबी कॉर्प लि. दैनिक भास्कर प्रिंटिग प्लांट, 12 इंद्रा सर्किल, गठिलाखेडा, शारदा ड्रिम कॉलोनी के पास चितौड रोड़, भीलवाड़ा राजस्थान से मुदित। संपादकः पंकज गर्ग, कार्यालय नंबरः 01482-455184, मों. 9214417111, 8005910698, E-MAIL:namasterajasthan11@gmail.com, nrnews100@gmail.com